

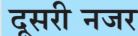
म

‘अधिनियम को धारा-8 के तहत सभी राज्यों द्वारा अधिसूचित योजना का नाम ‘विकसित भारत- गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी योजना’ होगा।’ यह नाम न केवल बोलने में बोझिल है, बल्कि गैर-हिंदी भाषी

गरीबों के लिए जीवन रेखा

इस अधिनियम का मूलमंत्र 'आजीविका सुरक्षा की गारंटी' था और इसको प्रमुख विशेषताएँ थीं—

- यह योजना सार्वभौमिक, मांग-आधारित और पूरे वर्ष उपलब्ध थी।
- रोजगार की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी।



पी चिदंबरम

महिला श्रमिकों के पक्ष में एव
स्वागतयोग्य शुकाव आया।

मनरेगा की मूल भावना के विपरी

जो एक भ्रम है। अधिसूचित व्यस्तता लाकर एक साल में साठ दिन का होट नहीं कराया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता फीसद जितना कम हो सकता है और कई शर्तों से थिरा होगा। केंद्र सरकार उससे विधेयक *संघीय विरोधी* बन जाते

स्मृति से मिटाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक समझ कहती हैं यह आपत्ती (यापीया समझ)

नए विधेयक में खासियों के साथ ही यह कदम महात्मा गांधी को राष्ट्र की स्मृति से मिटाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, जो निंदनीय है। भाजपा की गणना के अनुसार, स्वतंत्र भारत का इतिहास 26 मई, 2014 से शुरू हुआ। अतीत को मिटाना ही होश- जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ यह सिलसिला अद्य महात्मा गांधी तक पहुँच गया है। भाजपा की इन गंभीर गलतियों को भारत की जनता माफ़ नहीं करेगी।

मन मुताबिक घेरा

सं

इसी बीच वैनेलौ में दक्षिण भारत के एक राज्य की ससाधरी पार्टी की ओर से हाई कोर्ट में एक कसब डायर मी की पहाड़ी के पुणे में नितर पर वीर जलने के पथ में ऐदर मर अदेत के हिसातल पन पर 'महाविप्लव' जलने को कार्यजाली मुक्त कलने की खबर वैनेलौ में आकर एक वीर बहस वन जायत। एक पक्ष कहतल तल कि नो जय की कलम पर 'दुखम' चलना है, न्यायव्यक्तिक को 'डरना' है... दुसरे कहते रहे कि जय जय फैसला 'सोव्यव्यक्तिक' को बहसा देतल है। जलम में एक पक्ष कहतल है कि इसरो सारा है कि महारुतलल हिंदुओं की अपने हो जलम में पुजा कलने की आजादी नै। जलक पक्ष की दराल

होनामगवाना को न्यायवासी को इतना वाला और जन्तव विरोधी बताया। इसी बीच भाजपा ने पैतालीस वयं के पंकज सिंह को अपना 'राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष' चुनकर विश्व को चौंका दिया। इतना युवा अध्यक्ष किसी level के पास नहीं दिखाता। एक प्रवक्ता ने कहा कि यह भाजपा का युवाओं की आर्मजिमा है। साफ़ नहीं, सत्ता दल जल्प छोड़ने वाला नहीं। एक दिन एक बड़े विश्वीय दल की 'घोट घोर घड़ी छोड़' रैली में नेताओं के वक्ता के 'घोट घोर घड़ी छोड़... आज नहीं तो कल स' में बड़ी जगह बनाई। सत्ता प्रवक्ता को कि नहीं। नेता माफी मांगें। यह 'महज्जत को दुका



सुधीश पचौरी

ए क दिन कोलकाता में 'फुटबाल के भगवान' मेस्सी के दर्शन के लिए उनके प्रशंसकों में ऐसी होड़ मची कि सारा स्टैडियम दर्शनार्थियों की तोड़फोड़ का शिकार हुआ। नैनल में खेल विशेषज्ञों ने आयोजकों को शिवकारा की मेस्सी का आना, न आना बराबर हुआ।

इसी बीच, सिडनी में दो आतंकियों
‘हनुक्का’ उत्सव के दौरान गोली
बारसाकर पंद्रह यहूदियों को मौत के घाट
उतारने की खबर को चैनल-चर्चा में
दिया। एक एंकर ने कहा कि य
आस्ट्रेलिया का ‘जागो आस्ट्रेलिया जागो
का आह्वान है... कब तक ऐसी त
‘भट के कंधे’ फहरोगे। इस तरह कब त
बचाते रहोगे... इसकी आसतचना क्यों न
ने कहा कि यह निन्दनीय है।। सिड
चर्चा में एक मुस्लिम विद्वान ने कहा।
होता, तो हम ज़िन्दा नहीं रह सकते थे। ये
हैं, ये वातावरण विगाड़ते हैं।

फिर एक दिन एक राज्य के विपक्षी नेता ने बोल दिया कि सेना को किसी और काम में लगाओ... और इसके फलस्वरूप वे दो दिन चर्चा में छापे रहे। फिर 'राष्ट्रवादी' चैनलों ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार को एक साथ निशाने पर लिया, तो कई 'सत्ता प्रवक्ता' अचानक हस्तप्रभ से रह गए और तब समझ में आया कि चैनलों की बंदूक किसी वक्ता से नहीं की, बल्कि सत्ता की है।

एक दिन नीलीश कुमार ने निवृत्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम युवती के हस्तियों को खींचकर निरपराध ही निंदिताने हाकन को। पश्चात् उसकी ईश हाकन का बचाव करने और रखावितानी को और से बचाव करने में खड़े किए जाते रहे। अपने सुशानन बायू का कह फिले वही है कज? और इती सवतने में कुमि मी शिवराज सिंह मोहान ने 'मरगार' का नाम बचवतन/शिवराज भारत-जी राम जी' करके और संसद में पास करके सवतने 'जी राम जी' कहलवान दिव। सरकारी ने 'जी राम जी' का ऐसा पंथ बनाया कि अप आलोचना दिव। 'जी राम जी' बोलें और न कतें लो 'जी राम जी' बोलें।

अमेरिका ने जारी की दिवंगत जेफरी से संबंधित फाइलें

उल्लेख

टंप ने 30 दिन में सची जारी करने का आदेश दिया था

एपस्टीन फाइलों में भारत के आयुर्वेद का जिक्र

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए जिसमें 30 दिनों के भीतर संबंधित फाइल जारी करने का आदेश दिया गया था। यह मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, और डेमोक्रेट पार्टी के नेताओं द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली लोगों से अपने संबंधों के लिए जाने



ट्रंप और एपस्टीन के बीच अनबन होने से पहले उनके बीच कई वर्षों तक मित्रता रही थी, और यह संबंध एक बड़े राजनीतिक विवाद का विषय रहा है। न्याय विभाग द्वारा जारी की गई

मसाज' शीर्षक वाले लेख भी हैं, जिसमें लेखक के उपयोग का उल्लेख किया गया है। इन लेखों में छह तस्वीरें शामिल हैं, और न्याय विभाग ने कहा कि यह लेख किया गया दस्तावेजों का खुलासा अधूरा है।

इसमें कहा गया है कि पश्चिम में कई चिकित्सक अब भारत की इस 5,000 साल पुरानी प्राकृतिक उपचार प्रणाली पर आधारित मालिश और अन्य उपचार प्रदान कर रहे हैं।

एप्परीटीन से जुड़े किसी भी मामले में न तो ट्रंप और न ही क्लिंटन पर कभी कोई गलत काम करने का आरोप लगा है। मैनहट्टन जेल में मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए एप्परीटीन ने 2019 में आत्महत्या कर ली थी। उस पर दर्जनों नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और तस्करी का आरोप था।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र करते हुए रुबियो ने कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति स्थापना को दी प्राथमिकता

न्यूयार्क/वाशिंगटन, 20 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांतिदूत के तौर पर अपनी भूमिका को प्राथमिकता दी है। ट्रंप भारत एवं पाकिस्तान के बीच संघर्ष सुलझाने में अपनी भूमिका को लेकर कई बार दावा कर चुके हैं। वह अब तक लगभग 70 बार यह दावा कर चुके हैं।

रुबियो ने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और उसने ऐसे संघर्ष सुलझाने में भी भूमिका निभाई है जो अमेरिका के रोजमर्रा के जीवन के लिए संभवतः उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। रुबियो ने शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति ने शांतिदूत की भूमिका को प्राथमिकता



दी है और इसलिए आपने हमें वर्तमान की चुनौतियों जैसे कि रूस, यूक्रेन, भारत और पाकिस्तान या थाईलैंड और कंबोडिया के संघर्षों को समाप्त करने की कोशिश में अहम भूमिका निभाते देखा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा सुलझाए गए कुछ संघर्षों की जड़ें 'कई वर्षों पुरानी हैं, लेकिन हम इन्हें सुलझाने में सहायता करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले में 26 आम नागरिकों की मौत के बाद भारत ने छह-

सात मई की दरमियानी रात को 'आपरेशन सिंदूर' शुरू किया और पाकिस्तान एवं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया। चार दिनों तक जारी रहे सीमा पार ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान 10 मई को संघर्ष को समाप्त करने के लिए सहमत हुए। भारत ने संघर्ष के समाधान में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार किया है। रुबियो ने चीन और जापान को लेकर संबंधों से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि हम समझते हैं कि उस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम जापान के साथ अपनी मजबूत और ठोस साझेदारी एवं गठबंधन को जारी रखते हुए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीन सरकार के साथ भी मिलकर काम करने के व्यावहारिक और सकारात्मक रास्ते तलाश सकते हैं।

Jansatta Page No-7

इनकी कुल लागत करीब चार लाख करोड़ रुपए है

टिप्पणी

एक लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू नहीं हुईं

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रफ्तार धीमी

सुशील राघव
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं की रफ्तार सुस्त है। सरकार ने खुद माना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की 643 परियोजनाओं में निर्धारित समय सीमा से एक से तीन वर्ष की देरी हो चुकी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब चार लाख करोड़ रुपए है।

वहीं, एक लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 133 परियोजनाएं विभिन्न कारणों से अब तक शुरू हो नहीं पाई हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। गडकरी ने बताया कि 2015-16 के बाद स्वीकृत की गई 643 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अपनी निर्धारित समय सीमा

दस वर्ष में 245 फीसद बढ़ा टोल टैक्स संग्रह
लोकसभा में एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में गडकरी ने बताया कि देश में 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स संग्रह 245 फीसद बढ़ गया है। देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 17,759.28 करोड़ रुपए का संग्रह किया गया था। जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक टोल टैक्स संग्रह 61408.15 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। यह बढ़ोतरी 2.45 गुना है।



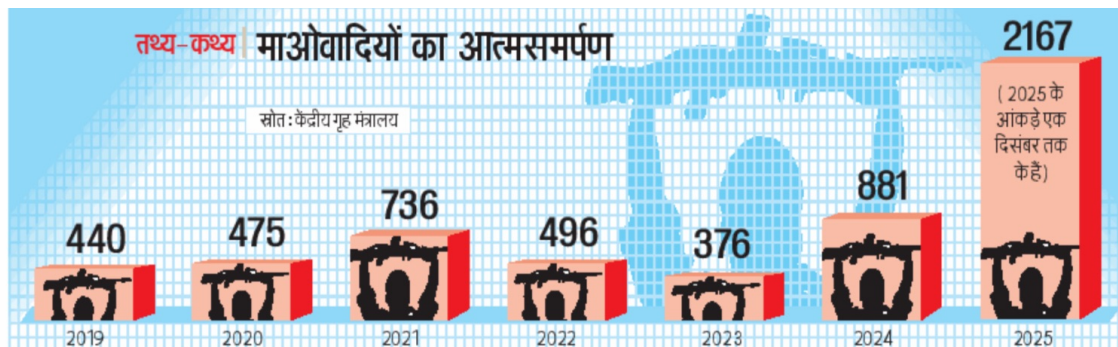
को पार कर चुकी हैं। इन निर्माणाधीन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग चार लाख करोड़ रुपए है। इनमें से 301 परियोजनाएं एक वर्ष से कम की देरी, 263 परियोजनाएं एक से तीन वर्ष की देरी, जबकि 79 परियोजनाएं तीन वर्ष से अधिक समय से लटकी हुई हैं। ये परियोजनाएं अब भी विभिन्न निर्माण चरणों को पूरा नहीं कर पाई हैं। मंत्री ने यह

भी बताया कि 133 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें आर्बिट्रिट तो कर दिया गया, लेकिन निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत के लिए तिथि हो घोषित नहीं हो सकी है। इन लंबित योजनाओं की कुल लागत लगभग एक लाख करोड़ रुपए है। मंत्रालय के अनुसार, इन पर काम शुरू न होने की प्रमुख वजहों में भूमि की उपलब्धता, वन एवं

वन्यजीव स्वीकृतियां और अन्य पूर्व-आवश्यक स्वीकृतियां शामिल हैं।

मंत्री ने बताया कि देरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 'भूमिराशि' पोर्टल, पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों के लिए 'पर्यावेश' पोर्टल में सुधार, रेलवे उपरिगामी पुल व भूमिगत पुल के डिजाइन की आनलाइन मंजूरी और राज्यों के साथ समन्वय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे ने भी रेलवे से संबंधित स्वीकृतियों के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है। मंत्री का कहना है कि इन उपायों की वजह से तीन वर्ष से अधिक देरी वाली परियोजनाओं की संख्या एक अप्रैल 2024 को 152 से घटकर 30 नवंबर 2025 तक 85 रह गई है, जबकि आर्बिट्रेंट के 12 महीने बाद भी तिथि न मिलने वाली परियोजनाएं 87 से घटकर 45 रह गई हैं।

Jansatta Page No-6



Dainik Jagaran Page No-8

तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में अदालत का फैसला इमरान, बुशरा बीबी को 17-17 साल की कैद

इस्लामाबाद, 20 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को 17-17 साल के कारावास की सजा सुनाई।

अगस्त 2023 से जेल में बंद खान (73) अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद से विभिन्न मुकदमों का सामना कर रहे हैं। तोशाखाना-2 मामला 2021 में खान और बीबी को सऊदी सरकार से मिले सरकारी उपहारों में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के प्रमुख खान फिलहाल बंद हैं। खान और बुशरा को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10-10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों पर 1.64-1.64 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया। फैसले में कहा गया है कि इस अदालत ने सजा सुनाते समय इमरान अहमद खान नियाजी की उम्र के साथ साथ यह तथ्य भी ध्यान में रखा कि बुशरा इमरान खान एक महिला हैं। इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लचीला रुख अपनाकर अधिक सजा की तुलना में कम सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा कि इस मामले में दोषियों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 382-बी (सजा के समय कारावास की अवधि को ध्यान में रखना) का लाभ दिया गया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 21 गवाह पेश हुए। फैसला सुनाए जाते समय खान और



अदालत ने दंपति पर 1.64-1.64 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया।

बुशरा अदालत में मौजूद थे। खान ने मामले में सीआरपीसी की धारा 342 के तहत दर्ज बयान में इन आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मामला फर्जी है। मामला जुलाई 2024 में दायर किया गया था और इसमें आरोप था कि खान और बीबी ने मूल्यवान वस्त्र, महंगी घड़ियां, हीरे और सोने के आभूषणों को तोशाखाना (राजकीय उपहार भंडार) में जमा किए बिना बेच दिया था।

वित्त राज्य मंत्री बिलाल अजहर कयानी ने 'जियो न्यूज' से कहा कि उपहारों को जमा नहीं किया गया, जबकि उन्हें कानूनी रूप से इन्हें जमा करना चाहिए था। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान जो तथ्य सामने आए, उनके अनुसार आभूषण की वास्तविक कीमत सात करोड़ रुपए थी, हालांकि, इसका मूल्यांकन 58-59 लाख रुपए किया गया था। तोशाखाना कैबिनेट प्रभाग के तहत काम करने वाला एक विभाग है जो दूसरे देशों के शासन प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की ओर से पाकिस्तानी शासकों व सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले उपहारों को रखता है। तोशाखाना में उपहार जमा होने के बाद, उन्हें उचित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत खरीदा जा सकता है।

सिलाव खाजा : परतों वाली कुरकुरी मिठाई



संडे स्वाद

भारत हमेशा से ही खाने-पीने का शौकीन देश रहा है, जहां हर क्षेत्र के अपने खास व्यंजन हैं। उनमें से कुछ को जीआई टैग मिल चुका है, तो कुछ को इसका इंतजार है। ऐसे ही कुछ खास व्यंजनों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं 'संडे स्वाद' को। इस बार पेश है सिलाव का खाजा। बिहार की प्राचीन परतदार और कुरकुरी मिठाई, जिसका इतिहास 320 ईसा पूर्व तक जाता है। जीआई टैग हासिल कर चुकी इस लाजवाब मिठाई की कहानी पेश कर रहे हैं **रामारंकर कुमार**

मिठाइयां महज चीनी और खास सामग्री का मेल नहीं होतीं, बल्कि उनकी मिठास के पीछे कुछ रोचक कहानियां भी होती हैं। ये हमें परंपराओं से जोड़ती हैं और पुरानी यादों को ताजा करती हैं। सिलाव खाजा, ऐसी ही एक मिठाई है, जो हमें बिहार के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से रूबरू कराती है। मैदा, चीनी और घी से तैयार इस मिठाई की मांग सिर्फ शादी जैसे मांगलिक अवसरों पर ही नहीं, बल्कि कहीं-कहीं छठ पूजा में भी इसका विशेष स्थान है।

प्राचीन काल से संस्कृति का हिस्सा

ऐसा माना जाता है कि यह मिठाई सबसे पहले बिहार के नालंदा जिले में स्थित सिलाव कस्बे में बनाई गई थी। ऐतिहासिक रूप से, इसे स्थानीय घरों में धार्मिक त्योहारों के दौरान प्रसाद के रूप में बनाया जाता था। समय के साथ यह मेहमानवाजी का प्रतीक बन गया। देखते-देखते यह इतनी लोकप्रिय हुई कि इसने बिहार और उसके बिहार के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली।

जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रसिद्ध ब्रिटिश पुस्तकालीन जेडी बेगलर, जिन्होंने 1872-73 में सिलाव का दौरा किया था, ने इस मिठाई का वर्णन किया है और उस किंवदंती

जीआई टैग ने दी कारोबार को उड़ान

सिलाव का खाजा बिहार की पहली मिठाई है, जिसे भारत सरकार से जीआई (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन) टैग मिला है। यह टैग मिल जाने से कारोबार को नयी रफ्तार मिल गई है, जिससे इसकी पहुंच विदेशों तक भी हो गई है। इससे लिए एक एप भी बनाया गया है, जहां आप खाजा से जुड़ी जानकारी पा सकते हैं और घर बैठे अपने लिए खाजा मंगा भी सकते हैं।

के बारे में लिखा है कि यह मिठाई राजा विक्रमादित्य के समय से चली आ रही है। एक अन्य मान्यता यह है कि जब भगवान बुद्ध राजगीर से नालंदा की यात्रा के दौरान सिलाव से गुजरे, तो उन्हें सिलाव का खाजा भेंट किया गया था।

दरअसल, बिहार के बिहारशरीफ से करीब 21 किलोमीटर दूर बिहारशरीफ-राजगीर मुख्य मार्ग के किनारे बसा सिलाव शहर 'खाजा' को मिठास के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस 52 परतों वाली खाजा मिठाई का मुरीद हर कोई है।

स्वाद ऐसा लाजवाब कि एक बार जो खा लेता है, वह बार-बार खाना चाहता है।

खाजा के विविध स्वाद

आपको बता दें कि सिलाव में खाजा की 200 से ज्यादा दुकानें हैं और 15 हजार से ज्यादा परिवार इस कारोबार से जुड़े हैं। गुड का 300 तो चीनी का खाजा 250 रुपये किलो है। जबकि, देसी घी से तैयार खाजा की कीमत 1300 रुपये किलो है। राजाजी और सिलान आठ से नौ लाख का कारोबार होता है।

सिलाव के हुनरमंद कारीगर खाजा की पांच वेरिएटी तैयार करते हैं। चीनी, गुड़, नमक, खाद और चॉकलेट। खास यह कि यहां तैयार खाजा की गुणवत्ता तीन महत्त्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है। विदेशों से आर्डर आने पर थर्मोकॉल के डिब्बों में खाजा को पैक कर भेजा

जाता है, ताकि इसकी मिठास और स्वाद बरकरार रहे। अब तक यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, स्पेन, चीन, अमेरिका, लंडन, पाकिस्तान, कतर आदि देशों में खाजा की खपत बढ़ी है।



मेरे दादा श्री काली साह ने सिलाव में खाजा बनाने की शुरुआत की थी। तब से अब तक उनकी पांच पीढ़ियां इस कारोबार से जुड़ी हैं। वर्ष 1987 में मंत्रीशस में हुए अंतरराष्ट्रीय मिठाई महोत्सव में सिलाव के खाजा को अंतरराष्ट्रीय मिठाई का अवॉर्ड भी मिल चुका है।

—संजीव कुमार, खाजा के कारोबारी

शादी-विवाह के मौसम में खाजा कारोबार काफी बढ़ जाता है। राजगीर, नालंदा और पावापुरी के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने आने वाले सैलानी सिलाव खाजा खरीदना नहीं भूलते। यहां खाजा मॉल भी खोला गया है, जहां बैठकर अलग-अलग तरह के खाजा का स्वाद लिया जा सकता है।

संजीव कुमार, हुनरमंद

Hindustan Page No-21

तैयारी : राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपने खर्च से बनाएगी बिहार में निजी साझेदारी से एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में निजी साझेदारी से एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। पथ निर्माण विभाग एक्सप्रेसवे बनाने को उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला अपना सकता है। राज्य सरकार ने सात निश्चय-3 में घोषित पांच एक्सप्रेसवे को मूर्त रूप देने की कवायद शुरू कर दी है।

देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे अभी उत्तर प्रदेश में हैं। इसलिए राज्य सरकार ने यूपी को ही मॉडल मानकर एक्सप्रेसवे बनाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल, हाल ही में राज्य सरकार ने सात निश्चय-तीन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। सात निश्चय-3 में पांच एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। 2030 तक एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का लक्ष्य तय है। इसे मूर्त रूप देने के लिए पथ निर्माण विभाग ने हाल ही में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

इसमें यह उभरकर आया कि देश में अभी मात्र नौ एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें से एक बिहार (पटना-पुर्णिया) का है। सभी को नेशनल एक्सप्रेसवे दर्जा प्राप्त है। इसका अर्थ हुआ कि इसकी लागत राशि केंद्र सरकार वहन करती है। वहीं,

07 निश्चय-3 में घोषित पांच एक्सप्रेसवे को मूर्त रूप देने की कवायद शुरू

■ राज्य सरकार की गारंटी पर वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेकर होगा निर्माण



एक स्वतंत्र प्राधिकार का हो सकता है गठन

उत्तर प्रदेश मॉडल का अध्ययन करने पर पता चला कि यूपी ने सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण किया। राज्य सरकार ने इसके लिए बजटीय व्यवस्था की थी। लेकिन, इसकी लागत राशि को देखते हुए राज्य सरकार ने यूपी एक्सप्रेसवे प्राधिकार का गठन किया। प्राधिकार के माध्यम से सरकार केवल गारंटर बन रही है। सरकार की गारंटी पर वित्तीय संस्थानों से आसानी से कर्ज मिल जा रहे हैं। एनएच की तर्ज पर स्टेट एक्सप्रेसवे पर टोल की वसूली कर लागत राशि की वसूली होती है। इससे सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है। बिहार में भी एक्सप्रेसवे प्राधिकार या कोई स्वतंत्र प्राधिकार बनाने पर विचार चल रहा है।

राज्य सरकार की ओर से बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे को स्टेट एक्सप्रेसवे का दर्जा मिलता है। उत्तर प्रदेश में 14 स्टेट एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। इसमें चार यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल

ये पांच एक्सप्रेसवे बनेंगे

1. पटना-पुर्णिया
2. गोरखपुर-सिलीगुड़ी
3. रक्सौल-हल्द्वी
4. बक्सर-भागलपुर
5. वाराणसी-कोलकाता

कई विभाग मिलकर तय करेंगे एक्सप्रेसवे का मार्ग

एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का मकसद केवल लोगों को सहज, सुगम व तेज यातायात प्रदान करना ही नहीं बल्कि राज्य में विकसित हो रहे नए-नए इलाकों को सम्पर्कता और औद्योगिक वातावरण को और बेहतर करना भी है। इसलिए पथ निर्माण विभाग, नगर विकास, उद्योग विभाग आदि विभागों से विमर्श कर एक्सप्रेसवे का मार्ग तय होगा। मुख्य सचिव के स्तर पर होने वाली बैठक में मार्ग तय होने पर सरकार से मंजूरी ली जाएगी।

छह या आठ लेन के होते हैं

बिहार में अभी पांच एक्सप्रेसवे पटना-पुर्णिया, गोरखपुर-सिलीगुड़ी, रक्सौल-हल्द्वी, बक्सर-भागलपुर और वाराणसी-कोलकाता पर काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे की ऊंचाई सामान्य सड़क से अधिक होती है। इस पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां चलीती हैं। इनमें प्रवेश और निकास के लिए विशेष रेम्प का निर्माण होता है। आमतौर पर एक्सप्रेसवे छह या आठ लेन के होते हैं।

Hindustan Page No-3

वन्यजीवों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा

कंपनियों के सामाजिक उत्तरदायित्व में पर्यावरणीय जिम्मेदारी अनिवार्य

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को कारपोरेट पर्यावरणीय जिम्मेदारी से अलग नहीं किया जा सकता और कंपनियां पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य जीवों की अनदेखी कर खुद को सामाजिक रूप से जिम्मेदार नहीं कह सकतीं।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एसएस चंद्रकर की पीठ ने लुप्तप्राय प्रजाति गोडावण ('ग्रेट इंडियन बस्टर्ड') के संरक्षण के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए। यह प्रजाति राजस्थान और गुजरात में गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के संचालन के कारण खतरे में है। पीठ ने कहा कि 'इसलिए 'सामाजिक उत्तरदायित्व' की कारपोरेट परिभाषा में पर्यावरणीय जिम्मेदारी शामिल होनी चाहिए। कंपनियां पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य जीवों के समान दावों की अनदेखी करते हुए स्वयं को सामाजिक रूप से जिम्मेदार नहीं कह सकतीं।'

संविधान के अनुच्छेद 51ए(जी) के तहत वन, झीलों, नदियों और वन्यजीवों समेत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना तथा सभी जीवों के प्रति करुणा रखना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। पीठ ने कहा कि सीएसआर निधि इस कर्तव्य की मूर्त अभिव्यक्ति है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए धन का आवंटन स्वेच्छिक दान नहीं, बल्कि एक संवैधानिक दायित्व की पूर्ति है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत संसद ने इस कर्तव्य को संस्थागत रूप दिया है, जिसके जरिए कंपनियों के लिए उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत विशिष्ट वित्तीय



मानक अनिवार्य किए गए हैं। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान इस सिद्धांत को संहिताबद्ध करता है कि कारपोरेट लाभ केवल शेयरधारकों की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि उसका एक हिस्सा उस समाज का भी है, जो इस लाभ को संभव बनाता है। उसने कहा कि ऐतिहासिक रूप से निदेशकों का मुख्य कर्तव्य शेयरधारकों के लाभ को अधिकतम करना था, लेकिन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166(2) ने इस संकीर्ण दृष्टिकोण को बदलते हुए व्यापक न्यासी दायित्व निर्धारित किया है।

पीठ ने कहा कि अब निदेशकों पर यह कानूनी दायित्व है कि वे न केवल सदस्यों के लिए, बल्कि कंपनी, उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदाय और पर्यावरण संरक्षण के सर्वोत्तम हित में सद्भावना से कार्य करें। यह महत्वपूर्ण विस्तार इस तथ्य को स्वीकार करता है कि एक निगम समाज की एक इकाई है और उसकी 'सामाजिक' जिम्मेदारी उसके कार्यों से प्रभावित होने वाले व्यापक समुदाय के प्रति भी है। जहां खनन, विद्युत उत्पादन या

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एसएस चंद्रकर की पीठ ने लुप्त प्राय प्रजाति गोडावण ('ग्रेट इंडियन बस्टर्ड') के संरक्षण के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए। यह प्रजाति राजस्थान और गुजरात में गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के संचालन के कारण खतरे में है। पीठ ने कहा कि 'इसलिए 'सामाजिक उत्तरदायित्व' की कारपोरेट परिभाषा में पर्यावरणीय जिम्मेदारी शामिल होनी चाहिए। कंपनियां पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य जीवों के समान दावों की अनदेखी करते हुए स्वयं को सामाजिक रूप से जिम्मेदार नहीं कह सकतीं।'

बुनियादी ढांचा जैसी कारपोरेट गतिविधियां संकटग्रस्त प्रजातियों के आवास को खतरे में डालती हैं, वहां 'प्रदूषक भुगतान करें' सिद्धांत लागू होता है और कंपनी को प्रजाति संरक्षण की लागत वहन करनी होगी।'

पीठ ने कहा कि संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा सर्वोपरि दायित्व है और कारपोरेट कर्तव्य केवल शेयरधारकों की रक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा इसमें शामिल होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि राजस्थान और गुजरात के प्राथमिक और गैर-प्राथमिक क्षेत्रों में कार्यरत गैर-नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वे गोडावण के साथ पर्यावरण साझा करते हैं और उन्हें यह सोचकर काम करना चाहिए कि वे उसके आवास में अतिथि हैं।

यह आदेश पर्यावरणविद् एमके रंजीत सिंह द्वारा 2019 में दायर याचिका पर सुनाया गया, जिसमें गोडावण के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने का अनुरोध किया गया है।

उद्योग जगत ने पकड़ी रफ्तार, 15 हजार एकड़ का भूमि बैंक तैयार

अलविदा 2025

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में उद्योग ने इस वर्ष तेज रफ्तार पकड़ ली है। एक ओर बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव आए, वहीं कई नए उद्योग भी लगे। इथेनॉल के साथ-साथ कई सेक्टर में कारखाना लगाए जा चुके हैं। इस साल राज्य सरकार ने 15 हजार एकड़ का भूमि बैंक भी तैयार कर लिया। हर प्रखंड के लिए स्थानीय विशेषता लेते हुए वहां के एक उत्पाद का चयन किया गया। इसे स्थानीय

वाजार के साथ-साथ वैश्विक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार में अबतक एक लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव आ चुका है। इस राशि के माध्यम से चार हजार से अधिक परियोजनाएं स्थापित करने की योजना पर इस साल काम प्रारंभ हो गया। माना जा रहा है कि इस राशि से 10-15 लाख नौकरी व रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। वहीं अप्रत्याश रूप से भी पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। विभाग ने नए उद्योगों के साथ-साथ बंद पड़े उद्योगों को दोबारा शुरू करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके लिए उसने विषयवार एमनेस्टी नीति 2025 जारी की है। इसके तहत वैसी इकाइयां



250 एकड़ के विशेष आर्थिक ज़ोन को मंजूरी

बिहार में 250 एकड़ का विशेष आर्थिक ज़ोन (सेज) तैयार होगा। इन पर 226 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केन्द्र सरकार ने इसके निर्माण को मंजूरी दी। इसके तहत दो अलग-अलग सेज की स्थापना की जाएगी। ये 125-125 एकड़ क्षेत्र में बनाए जाएंगे। दोनों के लिए जमीन विहित कर ली गयी है। जल्द ही यहां काम शुरू होगा। उद्योग विभाग इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रहा है।

इस साल अबतक 18 हजार नौकरियां

इस साल अबतक बिहार के उद्योगों में लगभग 18 हजार युवाओं को नौकरी मिली। सूबे में औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ने के बाद नौकरी के अवसर बढ़ने लगे हैं। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के लागू होने के बाद पिछले नौ वर्षों में 42 हजार युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। समीक्षा के दौरान यह बात भी सामने आई कि बिहार को औद्योगिक इकाइयों में वर्ष 2022-23 से हर साल नौकरी की संख्या दोगुनी से अधिक हो जा रही है। जितनी नौकरी वर्ष 2022-23 में मिली, उससे दोगुनी नौकरी वर्ष 2023-24 में मिली। यह क्रम इस साल भी जारी है।

बिहार में 250 एकड़ का विशेष आर्थिक ज़ोन (सेज) तैयार होगा। इन पर 226 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केन्द्र सरकार ने इसके निर्माण को मंजूरी दी। इसके तहत दो अलग-अलग सेज की स्थापना की जाएगी। ये 125-125 एकड़ क्षेत्र में बनाए जाएंगे। दोनों के लिए जमीन विहित कर ली गयी है। जल्द ही यहां काम शुरू होगा। उद्योग विभाग इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रहा है।

जो काफी समय से बंद या खाली पड़ी हैं, उनकी औद्योगिक भूमि को फिर से उद्योग के काम में लाना है। इससे बंद पड़ी उद्योगों को दोबारा शुरू करने का

मौका दिया जाएगा। **सिंगल विंडो सिस्टम प्रभावी:** उद्योग विभाग का सिंगल विंडो सिस्टम पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावी हुआ है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, जहां निवेशक अपनी सारी आवश्यक स्वीकृतियों के लिए एक ही जगह आवेदन कर सकते हैं। हर

फोकस ग्रीन टेक्नोलॉजी पर

बिहार अब भविष्य को देखकर ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। सूबे में ग्रीन टेक्नोलॉजी से गांवों व छोटे शहरों की चूरा बदलने की रणनीति है। इसके लिए राज्य सरकार ने ग्रीन टेक्नोलॉजी पर गंभीरता से काम शुरू किया है। विश्वस्तर की टेक्नोलॉजी गांवों व छोटे शहरों में पहुंचाने की कार्ययोजना तैयार है। नयी औद्योगिक नीति में इस पर काम किया जा रहा है। इसके फलते बिहार ग्रीन इंडस्ट्री के लिए तैयार हो रहा है।

आवेदन को निश्चित समय सीमा के अंदर निपटाने का प्रावधान है। निवेशक ऑनलाइन अपने आवेदन को प्रगति ट्रैक कर सकते हैं।

बिहार को नया टेक हब बनाने की शीर्ष समिति बनी

बिहार को पूर्ण भारत का नया टेक हब बनाने के उद्देश्य से डिजिटल कोरिडोर, सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग पार्क, स्मॉल कैपेसिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी एवं फिन्टेक सिटी की स्थापना को कार्य योजना के निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन के सतत अनुश्रवण के लिए शीर्ष समिति का गठन किया गया। सब हो बिहार को एक वैश्विक-कैप इंड हब एवं स्मॉल टेक वर्ल्स के रूप में विकसित एवं स्थापित करने को कार्य योजना बनाकर उसके कार्यान्वयन के लिए सतत अनुश्रवण करने के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा प्रतिभाशाली युवाओं एवं उद्यमियों को रणनीतिक दृष्टिकोण एवं अलग-अलग एजेंडों में बिहार के विकास के लिए कार्य योजना बनाकर उसके कार्यान्वयन एवं सतत अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है।

तीन साल में 3.5 गुना बढ़े कम नामांकन वाले विद्यालय

घटी संख्या

पटना, कार्यालय संवाददाता। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। इस कारण विद्यालयों की संख्या भी घटती जा रही है। पिछले तीन वर्षों में 10 या उससे कम बच्चे नामांकित वाले स्कूलों की संख्या लगभग 3.5 गुना बढ़ गई है। विद्यार्थियों की कम संख्या और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से एक साल में 1783 स्कूलों का विलय किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में पिछले तीन वर्षों में 10 या उससे कम नामांकन वाले स्कूलों की संख्या वर्तमान में 225 से बढ़कर

10 या उससे कम नामांकन वाले स्कूल-शिक्षक की संख्या

वर्ष	संख्या	शिक्षक
2022-23	225	1046
2023-24	534	2539
2024-25	730	3600

10 या उससे कम बच्चे नामांकन वाले 1783 स्कूलों का विलय

77856 से घटकर 76073 हुए सरकारी स्कूल

730 हो गई है।

निरीक्षण के दौरान स्कूलों की होगी जांच

: तीन जिलों में एक-एक स्कूल ऐसे भी हैं, जहां एक भी बच्चा नामांकित नहीं है। इनमें भागलपुर, कटिहार और



राज्य के तीन जिलों में एक-एक स्कूल ऐसे जहाँ एक भी छात्र नहीं

पिछले एक साल में सरकारी स्कूलों की संख्या 77856 से घटकर 76073 हो गई है। बिहार के बक्सर जिला को छोड़

पूर्वी चंपारण जिला शामिल हैं। लेकिन स्थिति यह कि इन 10 और उससे कम नामांकन वाले 730 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 3600 है। वर्ष 2022-23 में ऐसे कम नामांकन

दोहरे नामांकन वाले 3.5 लाख से अधिक बच्चों का नाम कटा

स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या का एक प्रमुख कारण बच्चों की आधार कार्ड सीडिंग है। शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जब विद्यालयों में नामांकित बच्चों के आधार कार्ड मांगे तो विभाग को कई दोहरे नामांकन वाले बच्चों की जानकारी मिली। तीन लाख से अधिक बच्चों का नाम दोहरे नामांकन की

वजह से सरकारी स्कूलों से काटा गया। इनमें पटना जिले के भी लगभग नौ हजार बच्चे शामिल थे। सरकारी स्कूल में मिलने वाली योजनाओं का लाभ उठाने के कारण इन बच्चों ने दो-दो जगहों पर नामांकन करा रखा था। आधार कार्ड जोड़ने की प्रक्रिया में जब मामले उजागर हुआ तो ऐसे बच्चों के नाम काट दिए गए।

कर सभी जिलों में स्कूलों की संख्या घटी है। बक्सर जिले में 23 स्कूल बढ़े हैं।

वाले स्कूलों की संख्या केवल 225 थी। जहां 1046 शिक्षक थे। यह संख्या 2023-24 में बढ़कर क्रमशः 534 और 2539 हो गई जबकि 2024-25 में यह और भी अधिक बढ़कर 730

स्कूलों तथा 3600 शिक्षकों पर पहुंच गई है। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान ऐसे स्कूलों की जांच की जाएगी। कम नामांकन के पीछे के कारणों का पता लगाया जाएगा।

वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत को लचीला बने रहना चाहिए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 दिसंबर।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य 'गठबंधन की राजनीति' की तरह है, जहां निष्ठाएं लगातार बदलती रहती हैं। भारत को ऐसे परिदृश्य में लचीला रख अपनाते हुए अपने हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत को पहले की तुलना में कहीं अधिक सकारात्मक रूप में देखती है और देश की छवि में आया यह बदलाव एक निर्विवाद सच्चाई है। जयशंकर ने पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड विश्वविद्यालय) के 22वें दीक्षांत समारोह में कहा कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि शक्ति और प्रभाव के कई केंद्र उभर चुके हैं और अब कोई भी देश, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, सभी मुद्दों पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता।

जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया हमें किस तरह से देखती है? इसका संक्षिप्त उत्तर यह है



उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है।

कि पहले की तुलना में कहीं अधिक सकारात्मक और कहीं अधिक गंभीरता से। इसका कारण हमारा राष्ट्रीय ब्रांड और हमारी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दोनों हैं, जिनमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

विदेश मंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारतीयों को मजबूत कार्य-नैतिकता वाले, प्रौद्योगिकी में दक्ष और परिवार-केंद्रित संस्कृति को अपनाने वाले लोगों के रूप में देखती है। विदेश में संवाद के दौरान मैं हमारे प्रवासी भारतीयों के बारे में अक्सर प्रशंसा के शब्द सुनता हूँ। भारत में कारोबार करना आसान हो रहा है और जीवन-यापन में सहूलियत बढ़ रही है। इसी के साथ एक व्यक्ति, राष्ट्र और समाज

के रूप में भारत के बारे में पुरानी रूढ़िवादी धारणाएं धीरे-धीरे पीछे छूट रही हैं। जयशंकर ने कहा कि प्रगति और आधुनिकीकरण की अपनी यात्रा में बेशक हमें अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन हमारी छवि में यह बदलाव ऐसी वास्तविकता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे आंकड़े इस परिवर्तन की पुष्टि करते हैं। मंत्री ने कहा कि शायद अन्य किसी चीज से अधिक, आज भारत को उसकी प्रतिभा और कौशल से परिभाषित किया जाता है। इन सभी ने हमारे राष्ट्रीय ब्रांड को आकार देने में मदद की है। जयशंकर ने कहा कि हम भारतीय दुनिया से किस तरह संपर्क करते हैं? मैं फिर से स्पष्ट रूप से कहूंगा- पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास और क्षमता के साथ।

उन्होंने कहा कि लेकिन एक अंतर पर ध्यान देना जरूरी है। अधिकतर देशों ने व्यापार, निवेश या सेवाओं जैसे आर्थिक संपर्कों के माध्यम से दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। स्वाभाविक रूप से यही हमारा मार्ग भी रहा है और इन सभी पैमानों पर निरंतर विकास हुआ है।

Jansatta Page No-2

विकास को धरातल पर उतारकर स्वयं को साबित करना चाहती हैं साक्षी

उत्तराखंड में सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान हैं पौड़ी की 22 वर्षीय साक्षी रावत।

नेतृत्व

वह बीटेक डिग्रीधारी हैं। नई पौड़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए वह ग्राम पंचायत हुई को सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक स्तर पर आगे बढ़ाने का खाका खींच रही हैं। जानिए इनके बारे में:

विनय बहुगुणा • जागरण

श्रीनगर गढ़वाल: पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत हुई की निबंधित प्रधान 22 वर्षीय साक्षी रावत बीटेक डिग्रीधारी हैं। पदभार ग्रहण करने के साथ ही वह ग्राम पंचायत में सुविधाओं को धरातल पर उतारने में जुट गई हैं। कुछ दिन पूर्व वह जिलाधिकारी गढ़वाल स्वाति एस भटौरिया को ग्राम पंचायत में विकास के रोडमैप से भी अवगत करा चुकी हैं। हुई गांव के जसबीर सिंह और पुष्पा देवी रावत को तीन संतानों में दूसरी

साक्षी उत्तराखंड में सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान हैं। इन दिनों वह उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में वर्षाकाल के दौरान क्षतिग्रस्त हुए रास्तों को मरम्मत कराने में जुटी हैं। साथ ही पंचायत को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर आगे बढ़ाने का खाका भी तैयार कर रही हैं। साक्षी चाहती थीं कि अपनी ग्राम पंचायत और क्षेत्र के लिए कुछ करें। ऐसे में परिवार के सहयोग और ग्रामीणों के प्रोत्साहन से उन्होंने प्रधान का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की।

पल्लव बना विकसित समस्या : साक्षी



जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस. भटौरिया से भेंट करती ग्राम प्रधान साक्षी रावत।

फूलों की खेती से नया आयाम

बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक की डिग्री प्राप्त करने वाली साक्षी रावत का कहना है कि कृषि उनकी पहली प्राथमिकता है। गांव में अनुपयोगी पड़े खेतों को उत्पादक बनाया जाएगा। इन खेतों में फूलों की खेती होगी। कौबो, ड्रैगन फ्रूट्स व सेब के साथ ही जड़ी-बूटी उत्पादन भी किया जाएगा। इसके लिए वह कृषि-वर्गाने विशेषज्ञों के संपर्क में हैं। ग्राम पंचायत हुई को सड़क से जोड़ने और पैक्जल के लिए कार्य करना है।

टूटी पगडंडियां करवा रही हैं ठीक

ग्राम पंचायत हुई में बीते अगस्त-सितंबर के दौरान हुई भारी वर्षा से पैदल रास्ते, खेत और अन्य परिसरों को व्यापक क्षति पहुंची थी। सो, इन दिनों साक्षी गांव के टूटे रास्तों की मरम्मत कराने में जुटी हैं। अन्य समस्याओं के निस्तारण का प्रयास भी कर रही हैं। वह कहती हैं कि ग्राम पंचायत के हर घर में शौचालय हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांव के हर तोक को रास्तों से जोड़ने का भी प्रयास हो रहा है।

ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत हुई सहित उत्तराखंड के कई गांवों में पलायन सबसे बड़ी समस्या है। पलायन के चलते खेती-किसानी खत्म हो रही है और अनुपयोगी हो चुके खेत जंगली जानवरों

का आशियाना बन रहे हैं। वह पहाड़ के लिए चिंता का विषय है। गांव में पानी की समस्या भी विकट है। ऐसे में जो लोग सब्जी या फलोंत्पादन को सोच रहे हैं, वह भी काम शुरू नहीं कर पा रहे। उन्होंने

जिलाधिकारी गढ़वाल व सीडीओ को अलकनंदा नदी से लिफ्ट पंपिंग के जरिये गांव तक पानी सप्लाई करने का प्रस्ताव भी सौंपा है, ताकि हुई सहित आसपास के गांवों को इसका लाभ मिल सके।

एपस्टीन से जुड़ी 13 हजार से ज्यादा फाइलें जारी, विलंटन घिरे

न्यूयार्क टाइम्स से

वाशिंगटन: अमेरिकी न्याय विभाग ने यौन तस्करी के आरोपी और वैश्वी ठहराए गए फाइनेंस् जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी 13,000 से अधिक फाइलें जारी कर दी हैं। यह कदम कांग्रेस के दबाव और पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित कानून के तहत उठाया गया। हालांकि, बहुप्रतीक्षित इन दस्तावेजों से कोई बड़ा खुलासा सामने नहीं आया है। इन बहुप्रतीक्षित फाइलों में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ध्यान हटाकर अन्य पर केंद्रित करने का प्रयास किया गया है।

जारी फाइलों में हजारों तस्वीरें, फोन रिकार्ड, यात्रा लाग और जांच से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर भारी रूप से संशोधित हैं। कई दस्तावेजों से एपस्टीन की गतिविधियों या प्रभावशाली लोगों से उसके संबंधों पर नई रोशनी नहीं पड़ी। एक 119 पन्नों की 'ग्रेड जूरी न्यूयार्क' फाइल पूरी तरह काली कर दी गई थी।

सार्वजनिक किए गए हजारों दस्तावेजों में विलंटन की कई तस्वीरें हैं। कुछ में वे

सार्वजनिक किए गए हजारों दस्तावेजों में विलंटन की कई तस्वीरें हैं

मुझे देखकर ट्रंप की नीयत बिगड़ी थी

फार्मर ने बताया कि 1995 में ट्रंप एपस्टीन के न्यूयार्क सिटी दफ्तर में आए थे। उस समय हाफ पैट में थी। ट्रंप मेरे नंगे पैरों की तरफ देखने लगे। तभी एपस्टीन कमरे में आया और ट्रंप से कहा, 'नहीं, नहीं। वह तुम्हारे लिए नहीं है।' इसके बाद दोनों कमरे से बाहर जाने लगे। फार्मर ने दावा किया कि उन्होंने ट्रंप को ये कहते सुना, 'मुझे लगा ये वही 16 साल वाली लड़की है।' फार्मर ने बताया कि एपस्टीन ने उसे किशोरियों की नमन तस्वीरें लेने का काम सौंप रखा था। इसे वह 'अर्टवर्क' कहता था। साथ ही वह धमकाता भी था कि तस्वीरों के बारे में शिकायत करने पर वह उसका घर जला डालेगा।

अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी की गई फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति विल विलंटन की कुछ तस्वीरें।



एक निजी विमान में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक में उनकी गोद में एक महिला बैठी है। विलंटन की सभी तस्वीरों में महिलाओं के चेहरे धुंधले कर दिए गए हैं। एक अन्य तस्वीर में वह एपस्टीन की सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल

और एक के अन्य महिला के साथ स्विमिंग पूल में हैं। एक अन्य तस्वीर में विलंटन हाट टब में महिला संग हैं।

एफबीआई की तलाशगी पड़ी सैकड़ों किशोरियों पर भारी : एपस्टीन के यहाँ काम करनेवाली एक महिला ने 1996 में

एफबीआई से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शिकायत की थी, लेकिन तब एजेंसी ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। इसके एक दशक बाद एफबीआई ने यौन अपराधों को लेकर एपस्टीन के खिलाफ छानबीन शुरू की थी।

Dainik Jagaran Page No-11

नीला ग्रह बना लाल रेगिस्तान

मुकुल व्यास

आज मंगल एक शुष्क लाल रेगिस्तान है, लेकिन अतीत में वह ऐसा नहीं था। अरबों साल पहले मंगल की सतह पर तरल पानी और एक वायुमंडल ने उसे नीली दुनिया दिया था। एक बड़ा सवाल यह है कि मंगल लाल रेगिस्तान में कैसे तब्दील हुआ? नासा का मावेन अंतरिक्ष यान इस समय मंगल के चारों तरफ घूम रहा है। उसने मंगल के बारे में जो नए आंकड़े जुटाए हैं उससे पता चलता है कि मंगल का वायुमंडल अरबों वर्ष से अंतरिक्ष में लौक हो रहा है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे एक समय की नीली दुनिया एक लाल रेगिस्तान बन गई। नई रिसर्च का नेतृत्व कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी में ग्रह भौतिकविद शैनन करी ने किया है। वह नासा के मावेन मिशन की प्रमुख जांचकर्ता हैं। मंगल ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है, जिसका अर्ध व्यास 3390 किलोमीटर है और एक दिन 24.6 घंटे का होता है। इसकी झुकी हुई घूमने की धुरी इसे ऐसे मौसम देती है जो हमारे मौसम से ज्यादा लंबे होते हैं,

मंगल का वायुमंडल अरबों वर्ष से अंतरिक्ष में लौक हो रहा है, जिससे यह नीले से लाल हो गया

क्योंकि ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में 687 पृथ्वी दिवस लगते हैं। नासा के अंतरिक्ष यान से ली गई तस्वीरों में प्राचीन नदी घाटियाँ, झील के बेसिन और 4800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एक घाटी प्रणाली दिखाई देती हैं जो क्रस्ट (पपड़ी) पर बनी हुई हैं। इस तरह का लैंडस्केप ज्यादा घने आसमान के नीचे लंबे समय तक सतह पर बहते पानी से ही संभव था।

अपने इतिहास की शुरुआत में मंगल ग्रह पर शायद एक मैग्नेटोस्फीयर (चुंबकीय मंडल) था। चुंबकीय मंडल किसी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जो सूर्य से आने वाले विद्युत चार्ज वाले कणों को मोड़ देता है। जब चार अरब साल पहले मंगल की चुंबकीय सुरक्षा खत्म हो गई, तो ऊपरी वायुमंडल सौर पवन की पूरी ताकत के संपर्क में आ गया। मंगल पर चल रही मुख्य पलायन प्रक्रिया 'एटमास्फेरिक

स्पटरिंग' कहलाती है, जिसमें ऊर्जावान कण वायुमंडलीय परमाणुओं से टकराते हैं और उन्हें अंतरिक्ष में धकेल देते हैं। मंगल ग्रह पर वे कण मुख्य रूप से सौर पवन के भारी आयन (एक या अधिक पाजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाले अणु) हैं जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर ऊपरी वायुमंडल में टकराते हैं। साथ ही, मावेन उपग्रह के अवलोकन से पता चलता है कि ऊपरी वायुमंडल में ले जाए गए पानी के अणु विखंडित हो जाते हैं और हाइड्रोजन छोड़ते हैं जो अंतरिक्ष में चली जाती है। मंगल पर रहने लायक स्थिति शायद ज्यादातर वायुमंडल के खत्म होने से पहले तक ही सीमित थी।

नासा के क्यूरियोसिटी, पर्सिवरेंस रोवर और मावेन उपग्रह अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह समय कितना लंबा चला। मंगल कैसे एक नीली दुनिया से लाल रेगिस्तान में बदल गया, यह समझ कर विज्ञानी यह तय कर पाएंगे कि दूर के बाहरी ग्रह अपने वायुमंडल और सतह के पानी को बनाए रख सकते हैं या नहीं।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

Dainik Jagaran Page No-8

अमेरिकी सेना ने सीरिया में आइएस के 70 से अधिक ठिकानों पर बोला हमला

वाशिंगटन, एनआइ : अमेरिकी और जार्डन की सेनाओं ने सीरिया में आइएस आतंकी समूह के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इसमें 70 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ये हमले अमेरिकी एफ-15 और ए-10 जेट विमानों के साथ-साथ अपाचे हेलीकॉप्टरों और हिमर्स राकेट प्रणालियों द्वारा किए गए थे। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि हमले रात भर चले। कमान ने हवाई हमलों का फुटेज जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर चैतावनी जारी करते हुए कहा कि आइएस पर पहले से कहीं ज्यादा करारा प्रहार किया जाएगा।

हाकआइ स्ट्राइक अभियान सीरिया के पल्मायरा में अमेरिकी और सीरियाई सेना के काफिले को आइएस हमलावर द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद चलाया गया है। ट्रंप ने कहा कि हमले सीरिया में इस महीने की शुरुआत में आइएस द्वारा दो अमेरिकी सैनिकों की हत्या के जवाब में किए गए हैं। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट

आतंकी हमले में दो अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद किया हवाई हमला
ट्रंप ने कहा, आइएस पर पहले से कहीं ज्यादा करारा प्रहार किया जाएगा

सीरिया में आइएस आतंकी समूह के खिलाफ अमेरिका की हाकआइ स्ट्राइक अभियान दौरान में उड़ान भरता केसी-135 स्ट्रेटोटेकर विमान। रायटर >>



हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका ने आइएस लड़ाकों, उनके बुनियादी ढांचे और हथियार ठिकानों को नष्ट करने के लिए आपरेशन हाकआइ स्ट्राइक शुरू किया है। यह किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है। यह प्रतिशोध की घोषणा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अपने नागरिकों की रक्षा करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा।

चैतावनी देते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों पर हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "आप दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों को निशाना बनाते हैं, तो अपनी जिंदगी के बचे हुए समय यह जानते हुए बिताएंगे कि अमेरिका आपका पीछा करेगा, ढूंढ निकालेगा और बेरहमी से मार डालेगा।"

Dainik Jagaran Page No-11

चार महीने से लगातार बढ़ रहा चीन को भारतीय निर्यात

अमेरिका की ओर से 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद भारत का पड़ोसी देश को बढ़ा निर्यात, लेकिन ज्यादा आयात अभी भी चुनौती

राजीव मुखर्जी • जागरण

नई दिल्ली: अमेरिका की ओर से 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद के पिछले चार महीनों से चीन को होने वाले भारतीय निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नवंबर 2025 में तो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में चीन को निर्यात 90 प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन अब भी चीन से होने वाला आयात काफी अधिक है। इसे देखते हुए चालू वित्त वर्ष 2025-26 में चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से अधिक रह सकता है। चालू वित्त वर्ष में (अप्रैल-नवंबर 2025) भारत ने चीन से 84 अरब डॉलर का आयात किया है। इस अवधि में चीन की निर्यात 12.22 अरब डॉलर का निर्यात किया गया है।

विदेश व्यापार के जनकरी के मुताबिक, सिर्फ चार उत्पादों का घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग बढ़कर भारत अपने व्यापार घाटे को काफी हद तक कम कर सकता है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स व

● चालू वित्त वर्ष में 100 अरब डॉलर से अधिक रह सकता है चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा

● घरेलू घाटे को मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाकर चीन से आयात में कमी ला सकता है भारत



प्लास्टिक शामिल हैं। चीन से होने वाले कुल आयात में इन चार उत्पादों की हिस्सेदारी 70-75 प्रतिशत तक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भारत अब

भी मोबाइल फोन के कई कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, लैपटॉप, सोलर सेल व माइक्रो, लॉथियम आयन बैटरी जैसे उत्पादों के लिए काफी हद तक

मोबाइल फोन का बड़ा निर्यातक बना भारत

पिछले पांच सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यातक देश बन चुका है। इसके लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े कच्चे माल की जरूरत है जो घरेलू स्तर पर पूरी नहीं हो सकती है। मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े मशीनों के लिए भारत अभी भी चीन पर काफी निर्भर है। पिछले कुछ सालों से घरेलू स्तर पर मैन्यूफैक्चरिंग का विस्तार हो रहा है जिससे मशीनरी का आयात कम होत नहीं दिख रहा है। जानकारी का कहना है कि पिछले दो साल में क्वालिटी कंट्रोल नियम व अपने निर्माण में तेजी आने से भारत में चीन से होने वाले कई उत्पादों के आयात में गिरावट आई है।

अब भी सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को

50 प्रतिशत शुल्क के बावजूद अब भी अमेरिका ही भारत के निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार बन हुआ है। 50 प्रतिशत शुल्क से छूट के दायरे में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, खास तौर पर उपकरणों के मजबूत निर्यात की वजह से पिछले साल की तुलना में अमेरिका को निर्यात में बढ़ोतरी दिख रही है।

चीन के आयात पर निर्भर करता है। बाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक भारत से चीन को होने

वाले निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 32 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि चीन से होने वाले

चीन को निर्यात (अरब डॉलर में)

अप्रैल	1.21
मई	1.46
जून	1.63
जुलाई	2.20

अप्रैल-नवंबर में प्रमुख बाजारों को निर्यात (अरब डॉलर में)

अमेरिका	59.04
यूएई	25.49
नीदरलैंड	12.90
चीन	12.22
ब्रिटेन	8.93
जर्मनी	7.47

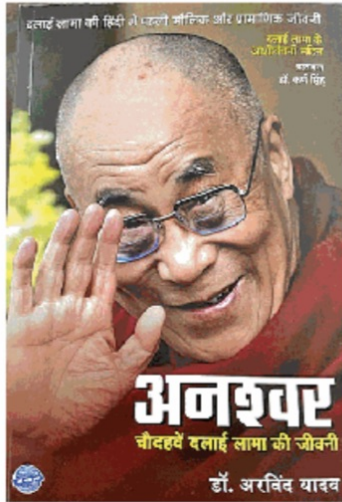
आयात में यह बढ़ोतरी 15 प्रतिशत रही है।

कैलेंडर वर्ष 2025 में जनवरी से नवंबर तक चीन से भारत ने 113 अरब डॉलर का आयात किया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स 38 अरब डॉलर, मशीनरी 25 अरब डॉलर, ऑर्गेनिक केमिकल्स 11.5 अरब डॉलर तो प्लास्टिक का आयात 6.3 अरब डॉलर रहा है। मालब 113 अरब डॉलर के आयात में इन चार उत्पादों का आयात 80 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के 38 अरब डॉलर के आयात में 8.6 अरब डॉलर का मोबाइल फोन कंपोनेंट्स, 6.2 अरब डॉलर का इंटीग्रेटेड सर्किट, 4.5 अरब डॉलर का लैपटॉप, 3.0 अरब डॉलर का सोलर सेल व माइक्रो, 2.6 अरब डॉलर का फैनल डिस्प्ले, 2.3 अरब डॉलर का लिथियम आयन बैटरी तो 1.8 अरब डॉलर का मेमोरी चिप आयात शामिल हैं। हालांकि इनमें से लैपटॉप, फैनल डिस्प्ले जैसे उत्पादों के घरेलू निर्यात का काम जल्द हो शुरू हो जाएगा।

दलाई लामा की अनश्वर यात्रा

तिब्बती मान्यता के अनुसार दलाई लामा करुणा के बोधिसत्व 'अवलोकितेश्वर' के अवतार माने जाते हैं, जो समस्त प्राणियों के दुख दूर करने के लिए बार-बार जन्म लेते हैं। 14वें पूज्य दलाई लामा (तेनजिन ग्यात्सो) स्वयं को साधारण बौद्ध भिक्षु कहते हैं, किंतु तिब्बत के इतिहास और आधुनिक विश्व की स्मृति में उनका स्थान ऐसे नेतृत्व के रूप में है, जो किसी एक देश या समुदाय तक सीमित न रहकर एक पूरी सभ्यता, उसकी आस्था और संघर्ष से जुड़ा हुआ है। डा. अरविंद यादव की 'अनश्वर' ऐसे असाधारण महापुरुष की जीवनी है, साथ ही तिब्बत के इतिहास का एक सशक्त दस्तावेज भी। तीन वर्ष के गहन शोध, दुर्लभ स्रोतों और प्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर लिखी गई यह कृति दलाई लामा को किसी मिथकीय आभा में नहीं ढालती, बल्कि तिब्बती समाज, बौद्ध परंपरा और वैश्विक राजनीति की पृष्ठभूमि में उनके असाधारण जीवन को गंभीर और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत करती है।

शुरुआत में दलाई लामा के जन्म (1935), गांववालों, माता-पिता, बहनभाइयों तथा गांव से राजधानी



पुस्तक: अनश्वर
लेखक: डा. अरविंद यादव
प्रकाशक: सर्व भाषा ट्रस्ट
मूल्य: 1495 रुपये

लहासा तक की लंबी यात्रा का वर्णन सजीव ढंग से हुआ है। उनके प्रशिक्षण काल में तिब्बत आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा था और चीन में माओ के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन हो चुका था। 1949 के बाद तिब्बत पर चीन की खुली दावेदारी के चलते दलाई लामा को 18 वर्ष की

आयु से पहले ही सत्ता संभालनी पड़ी। यहाँ 1939-1950 के बीच तिब्बत, चीन और विश्व-राजनीति में घटित घटनाओं को रेखांकित किया गया है।

एक साधारण किसान परिवार में जन्मा बालक ऐसी यात्रा पर निकला, जिसने उसे मठों की कठोर साधना, आध्यात्मिक अनुशासन और अंततः तिब्बत के धार्मिक-राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचाया। निर्वासन के बावजूद भारत में शरण लेकर (1959) अपनी सभ्यता को पुनः खड़ा करना और करुणा को ताकत में बदल देना इस जीवनी को गहरे अर्थों में प्रेरक बनाता है। भारत आगमन से लेकर 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने तक की यात्रा का वर्णन पुस्तक में अत्यंत रोचक है। दलाई लामा की पहचान से लेकर उनकी परीक्षा, संघर्ष, चुनौतियों, प्रेम और अहिंसा के संदेश के माध्यम से दुनिया का दिल जीतने की उनकी यात्रा इस ग्रंथ में कुल पांच भागों के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। यह ऐसे अनेक दुर्लभ तथ्यों और अनकहे प्रसंगों को उजागर करती है, जो अब तक किसी पुस्तक या आधिकारिक इतिहास का हिस्सा नहीं थे और जो यहाँ पहली बार सामने आते हैं।

Dainik Jagaran Page No-9

निर्माणाधीन रतले जलविद्युत परियोजना में कार्यरत 29 कर्मचारियों का आतंकी कनेक्शन

रतले नदी, जगमग • जम्मू
किशतबाद में विनाश नदी पर निर्माणाधीन 850 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजना में कार्यरत तौर पर आतंकी संरक्षण से जुड़े पूर्व आतंकी या आतंकीक पृष्ठभूमि वाले 29 लोग काम कर रहे हैं। यह जलविद्युत परियोजना के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए अगर इनकी गतिविधियों को लेकर जवाब भी नहीं देते तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। ऐसे कर्मियों को काम पर रखने के फैसले पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से निर्माण एजेंसी मेधा इंजीनियरिंग एंड इमैरल्टी लिमिटेड (एमईआइएल) को बर्खास्त कर पत्र लिखकर इस संबंध में चेतावनी दी गई। कुछ दिनों पहले ही इस परियोजना में कर्मियों को काम पर हुआ विवाद था। तब कर्मियों के एक अधिकांश ने स्वतंत्रता भाजपा जैसे विधायक पर कर्मचारियों को नियुक्ति में टकराव करने का आरोप बनाने का आरोप लगाते हुए काम बंद करने को धमकी दी थी। वहीं, विधायक

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने निर्माण एजेंसी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि कर्मियों के लिए काम नहीं शुरू होता तो निर्माण एजेंसी को 850 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना



विहिता में कोई आतंकवादी का बेटा तो कोई ओवरराउंड वर्कर

सूत्रों ने बताया कि विन 29 लोगों को विहिता किया गया है, उनमें से दो आतंकवादी के नाम पर सूचीबद्ध हैं। इनमें से तीन कर्मियों हुने आतंकी के रिश्तेदार हैं। एक ओवरराउंड वर्कर

का बेटा और एक आत्मसमर्पण कर चुके आतंकी का बेटा भी है। एक अन्य पर कमी के एक स्रोत को जानबूझकर बुला कर, नकली दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। 123 अन्य की आतंकवादी पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए

बताया गया है कि उन्होंने आम लोगों व स्वतंत्रता सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हुए कई निजी लोगों के सि भी खतरे पैदा किए हैं, कई बार कामगारों पर हमला कर सड़क पैदा

संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर पुलिस को देंगे सूचना

एमईआइएल के चौक आगरेटिंग अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र के पत्र की पुष्टि करते हुए कहा कि हमने जिला एक्सप्रेस को सूचित किया है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर रिपोर्ट की जाएगी। वहीं बातचीत की होटने की तो वह अभी समय नजर नहीं आता। हम किस कदम के तहत जांचें हुए, अगर किसी या कोई रिश्तेदार आतंकी है, या या हुआ या विवाद

कर्मचारी विवाद पर आगरे-सामने विधायक व अफसर

परियोजना में कर्मियों को रखने पर विरोध दिने हुए विवाद पर इलाहाबाद के और जिला कुल के 220 हैं। कर्मियों से आरोप है उस काम के बारे में नहीं जानते, जिसके लिए उन्हें रख गया है। विवाद के बाद से परियोजना में रखे गए अधिकांश कर्मियों को भोजन भेजने के खर्च में रख दिया है गया। मौजूब समय में खर्च 1.434

काम पर रखने से परियोजना को सुरक्षित रखने में आती है। जिला एक्सप्रेस ने पत्र में जलविद्युत परियोजना के सननीति व राष्ट्रीय महत्व का उल्लेख करते हुए बताया कि यह जूझन के निशाने पर है। इसीलिए ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों को काम पर रखने के फैसले पर पुनर्विचार जरूरी है। क्योंकि वे कुछ भी कर सकते हैं और ओवरराउंड के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। भाजपा नेता और विधायक ने कहा कि मैंने जो सबल उठाए थे, पुलिस ने उन्हें सही दायरा है। मैंने तो यही कहा था कि परियोजना में काम कर रहे कुछ लोग सही नहीं हैं, लेकिन मुझे पत्र पर परियोजना के काम में रुकावट डालने व माहौल खराब करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने कहा कि एमईआइएल के अधिकारियों अपने जमाने-जमाने से बचते हुए अपने नज़रबंदी दिवसों का खर्च करते हैं। एमईआइएल ने कुछ समय पहले ही नाम-पते का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इनके आतंकी संबंधों का आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को छिपते हुए इन

Dainik Jagaran Page No-5

विनम्रता कमजोरी नहीं

इ

ससे किसे इनकार होगा कि साहसी होना व्यक्तित्व का एक अहम गुण होना चाहिए। यह जीवन में आने वाली हर तरह की चुनौतियों का सामना करने से लेकर नए रास्ते तलाशने के लिए एक जरूरी कारक के तौर पर काम करता है। इस मूल्य में विश्वास करने वाला समाज निश्चित तौर पर व्यक्तित्व के एक सकारात्मक पक्ष पर विश्वास करता है। मगर साहस के इस मूल्य के भरोसे में आकर कई बार लोग विनम्रता को कमजोरी के तौर पर देखने लगते हैं। जबकि दिलचस्प यह है कि ऐसे लोगों में से कई इस बात में भी विश्वास करते हैं कि 'जब पेड़ फलों से लद जाता है, तो झुक जाता है।' आशय यह है कि अगर कोई साहसी है, वास्तव में बहादुर है, तो समाज और मानवीयता के हक में वह नैतिक मूल्यों की कद्र करेगा और इस तरह वह अपने व्यवहार में विनम्र होगा।

बाधाओं के बावजूद

अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति विनम्र हो, अपने सामने खड़ी की जाने वाली बाधाओं के बावजूद ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता हो, तो लोग उसे हल्का करके देखने लगते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं! दरअसल, हम जिस समाज में रहते हैं, उसमें वर्चस्व का मनोविज्ञान बड़े बारीक तरीके से काम करता है। इसमें एक पक्ष नाहक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता रहता है, जबकि दूसरा पक्ष नाहक ही अपने ऊपर बनने वाले दबाव के बावजूद विनम्रता की डोर को थामे रखता है। विडंबना यह है कि विनम्रता को मानवीय व्यवहार के लिए जरूरी मानने वाले व्यक्ति की क्षमताओं के आधार पर देखा जाना चाहिए, वहां उसे डरपोक या कमजोर व्यक्ति के तौर पर देखा जाने लगता है, यह मान कर कि उसके भीतर साहस और सामना करने की क्षमता का अभाव है।

मगर क्या सचमुच विनम्र लोग कमजोर होते हैं? ऐसा नहीं है। आमतौर पर विचार की बुनियाद पर खड़े व्यक्तित्व को संवेदना और मानवीय व्यवहारों की भी समझ होती है। वह अपनी ओर से किसी का दिल दुखाने से बचना चाहता

है और लोगों की कद्र उनकी क्षमताओं के आधार पर करना चाहता है। इस क्रम में विनम्रता किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बेहतर वाहक के रूप में काम करती है। मगर कई बार उसकी विनम्रता को कुछ लोग कमजोरी मानना शुरू कर देते हैं। इसके अपने कारण हो सकते हैं। मसलन, किसी विनम्र व्यक्ति को कमजोर समझने वाले व्यक्ति को शायद ही यह पता चल पाता है या इन कारणों की खोज करते हुए यह नहीं सोच पाता है कि दरअसल वह खुद एक तरह के दबाव में जीता है, उस पर गुलाम मानस हावी होता है, जो किसी की विनम्रता की शक्ति की पहचान कर पाने में सक्षम नहीं होता।

हकीकत यह है कि कामकाज की जगहों पर अगर विनम्रता को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाया जाए, तो यह सबसे आगे बढ़ने और विकास करने का रास्ता तैयार करती है। अक्सर कम समझदारी या असुरक्षाबोध की

वजह से विनम्रता को आत्मसम्मान या कमजोरी के भाव से जोड़ दिया जाता है और इसका कारण कमजोरी को माना जाता है। जबकि सच यह है कि अगर किन्हीं स्थितियों में विनम्र व्यक्ति का उपहास उड़ाने, उसकी क्षमताओं को खारिज करने का सिलसिला जारी रहता है, तो इस कुंठा का शिकार व्यक्ति धीरे-धीरे अपने भीतर की सकारात्मक क्षमताओं को खोता चला जाता है और आगे चल कर वह एक प्रकार की हीन भावना का शिकार हो जा सकता है।

असुरक्षाबोध का हासिल

यह कहा जाए कि विनम्र व्यक्ति को कमजोर समझना और उसका उपहास करना, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश का एक मुख्य कारण हीनभावना है, असुरक्षाबोध है, जिसमें ऐसा करने वाला व्यक्ति न केवल अपने भीतर की कुंठा का शिकार होकर सब कुछ खारिज करने की आदत से लाचार हो जाता है, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों के भीतर भी एक तरह का नकार-भाव या नकारात्मकता भर देता है। वह कई तरह की नकारात्मक ग्रंथियों का शिकार हो जाता है, बल्कि कार्यस्थल पर तो यह आदत कामकाज की गुणवत्ता पर बेहद प्रतिकूल असर डालती है।

अक्सर कम समझदारी या असुरक्षाबोध की वजह से विनम्रता को आत्मसम्मान या कमजोरी के भाव से जोड़ दिया जाता है। जबकि अगर किन्हीं स्थितियों में विनम्र व्यक्ति का उपहास उड़ाने, उसकी क्षमताओं को खारिज करने का सिलसिला जारी रहता है, तो इस कुंठा का शिकार व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी सकारात्मक क्षमताओं को खोता चला जाता है।

हकीकत यह है कि अगर कार्यस्थल पर व्यक्ति विनम्रता को अपना एक जरूरी हिस्सा माने तो न केवल वह अपने सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित समझदारी और संबंध विकसित कर सकता है, बल्कि इससे जिम्मेदारियों के निर्वाह के मामले में उत्पादकता में भी काफी इजाफा होता है।

विनम्रता की शक्ति

यह ध्यान रखने की जरूरत है कि विनम्रता किसी भी व्यक्ति के भीतर एक खास तरह की शक्ति के रूप में काम करती है। ऐसा व्यक्ति नाहक ही दूसरों पर हावी होने, नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है और इस तरह के कुत्सित दुराग्रहों से मुक्त रहता है, इसलिए संवेदनशील और उदार भी होता है। उदारता यहां तक भी कि वह अपने व्यक्तित्व की कमियों की भी ईमानदारी से पड़ताल कर पाता है, कमियों को स्वीकार करता है और फिर किसी सलाह से या फिर खुद उसकी पहचान करके उसमें सुधार करने की भी कोशिश करता है। यानी वह अपनी शक्तियों, हुनर, खूबियों और कमियों को लेकर ईमानदार रहता है।

विनम्रता की एक सबसे बड़ी खासियत यह भी होती है कि मानवीयता और संवेदनशीलता के समांतर यह नए विचारों और दृष्टिकोणों को लेकर भी उदार रहना सिखाती है। इससे दंभ या अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानने की कुंठा से मुक्ति मिलती है और साथ ही अपने आसपास मौजूद लोगों के प्रति जरूरी सहानुभूति और सहयोग की भावना को मजबूत करने में मदद करती है। अपना ईमानदार मूल्यांकन करने और खुद सुधार करते हुए आगे अपने लिए बेहतर रास्तों की खोज की शक्ति इसी भाव से आती है, जो खुद को अहंकार से दूर रखने में भी मददगार है।



विचार बोध

रोहित कुमार



लापरवाही की हद

दि

ल्ली के वायु प्रदूषण से मुझे इतनी तकलीफ हुई पिछले सप्ताह कि चाहूँ भी तो किसी दूसरे विषय पर लिखना असंभव है। पहली मुसीबत यह हुई कि मुंबई से दिल्ली मुझे तकरीबन बारह घंटे लगे घर तक पहुँचने में। मुंबई में घर से निकलने वाली थी कि एअर इंडिया से खबर आई कि उड़ान में एक घंटा देरी है। एक घंटे बाद संदेश आया मेरे फोन पर कि एक घंटा और देर होगी। उसके बाद जब कोई खबर नहीं आई, तो मैं पहुँच गई मुंबई हवाईअड्डा, जहाँ मालूम हुआ कि देरी एक घंटा और होने वाली है। मुझे तकलीफ तो हुई, लेकिन जब आसपास मैंने ऐसे लोगों को देखा जो मुझसे तीन घंटे पहले से हवाईअड्डे पर भटक रहे हैं दिल्ली की इस उड़ान के इंतजार में। मैं चुपचाप बैठ कर किताब पढ़ने लगी।

किताब अच्छी तो थी, लेकिन उसको पढ़ते-पढ़ते सारा दिन गुजर गया और अंत में दिल्ली पहुंची शाम होने के बाद। जबकि मुझे आना था दोपहर में। दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरने के बाद मालूम हुआ कि उस दिन सारी उड़ानें देर से चल रही थीं 'मौसम' की वजह से। जिस अधिकारी ने मुझे यह बताया, जब उससे पूछा कि मौसम का उसका मतलब प्रदूषण तो नहीं है, तो उसने माना कि प्रदूषण को ही वह मौसम कह रहा था। 'आप फिर भी ठीक हैं जी, आपको पता नहीं, कितनी उड़ानों को हमने चंडीगढ़ और जयपुर भेजा है मौसम की वजह से'।

हवाईअड्डे से बाहर आई, तो ऐसा लगा कि किसी डरावनी हिंदी फिल्म में गलती से पहुँच गई हूँ। प्रदूषण और कोहरे की ऐसी चादर बिछी हुई थी शहर पर कि मेरी गाड़ी रुक-रुक के ही चली इस गहरी चादर में से, जिसमें दूसरी गाड़ियों की बत्तियाँ दिख रही थीं कोहरे में लिपटी हुई। घर पहुँची तो पता लगा कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा हुआ है, जिसमें कोई बीस गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराई थीं 'मौसम' की वजह से। कई लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे।

अगले दिन मालूम हुआ कि जिस काम के लिए मैं दिल्ली आई थी, वह हो नहीं पाएगा।

इसलिए कि पुरानी गाड़ियों पर रोक लग गई है और दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि हर दफ्तर में आधे लोग घर से ही काम करें। मेरे लिए घर से काम करना संभव नहीं था, तो बैठ कर टीवी देखने लगी और देखते-देखते गुस्सा मेरा बढ़ता ही गया। पहला चेहरा जो देखा, वह दिल्ली सरकार के किसी मंत्री का था, जिसने प्रदूषण का सारा दोष पिछली सरकार पर डाला। उसकी बातें सुन कर याद आया कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तो किस



वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

पि

छले दो दशकों में प्रदूषण हर साल बढ़ता गया है। इसलिए कि भारत सरकार ने कभी कोशिश भी नहीं की है समझने की कि चीन ने वायु प्रदूषण का हल कैसे ढूँढा है। मुझे याद है बेजिंग जब गई थी कोई पंद्रह-बीस साल पहले, तो चीन की राजधानी का हाल बिल्कुल दिल्ली जैसा था। अब अगर नहीं है, तो इसलिए कि चीन की सरकार ने समाधान ढूँढा, सिर्फ बेजिंग के लिए नहीं, बल्कि उसके आसपास कोई तीस अन्य शहरों का भी।

आक्रामक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के लोग टीवी पर प्रदूषण की बातें करते थे। दोष लगाते थे कि पंजाब के किसानों के पराली जलाने से ही प्रदूषण बढ़ा है दिल्ली में और इसलिए कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी और केजरीवाल इसको रोक नहीं रहे हैं। कभी दोष किसानों पर डालते हैं हमारे शासक, तो कभी बेघर गरीबों के चूल्हों पर, लेकिन कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि असली दोष है भारत सरकार का।

पिछले दो दशकों में प्रदूषण हर साल बढ़ता गया है। इसलिए कि भारत सरकार ने कभी कोशिश भी नहीं की है समझने की कि चीन ने वायु प्रदूषण का हल कैसे ढूँढा है। मुझे याद है बेजिंग जब गई थी कोई पंद्रह-बीस साल पहले, तो चीन की राजधानी का हाल बिल्कुल दिल्ली जैसा था। अब अगर नहीं है, तो

इसलिए कि चीन की सरकार ने समाधान ढूँढा सिर्फ बेजिंग के लिए नहीं, बल्कि उसके आसपास कोई तीस अन्य शहरों का भी। साथ में कोयले का इस्तेमाल तकरीबन पूरी तरह बंद किया और शहरों में चलने वाली गाड़ियों पर सख्त पाबंदियाँ लगाईं।

मैंने चीन का हवाला देते हुए 'एक्स' पर लिखा कि हमको चीन से सीख लेनी चाहिए, तो पीछे पड़ गए भाजपा के समर्थक और कुछ ऐसे लोग जो अपने आपको हर चीज का विशेषज्ञ मानते हैं। जो सुनने को मिला, वह कुछ इस किस्म का था। 'आप चुप रहिए। आपको इन चीजों के बारे में इतना नहीं मालूम, जितना हमारे प्रधानमंत्री को मालूम है। वे कर रहे हैं जो कुछ हो सकता है'। 'बैठ जाओ आपको क्या मालूम इन चीजों के बारे में'। और जो थोड़े सभ्य मिजाज के थे उनसे यह सुना, 'चीन जो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हमारा देश लोकतांत्रिक है इसलिए'।

इनसे कौन भिड़ें, लेकिन हमारे-आपके लिए कहना जरूरी हो गया है कि वायु प्रदूषण जो इस तरह बढ़ गया है उत्तर भारत में, उसका दोष सीधा थोपा जा सकता है हमारे शासकों पर। इसमें बराबर का दोष बनता है राजनीतिकों और आला अधिकारियों का। इन लोगों ने लापरवाही ऐसी दिखाई है पिछले तीन दशकों में कि तकरीबन समाधान ढूँढने की कोशिश तक नहीं हुई है। नतीजा यह कि जो समस्या कभी सिर्फ दिल्ली की थी, वह फैलते-फैलते अब उत्तर भारत के हर शहर की हो गई है। इतनी गंभीर समस्या बन गई है कि शर्म आनी चाहिए इस देश के हर पर्यावरण मंत्री को। केंद्रीय मंत्री व्यस्त रहते हैं विदेश में पर्यावरण बचाओ सम्मेलनों में शामिल होने में, लेकिन राज्य सरकारों के पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे थे इस दौरान? क्या जानते नहीं थे कि अगर लोगों के लिए सांस लेना ही खतरनाक हो जाए, तो पर्यावरण को बचाने का कोई फायदा नहीं रहता है। आम लोग जब सांस लेंगे साफ वायु में, तब जाकर परवाह कर पाएंगे पर्यावरण बचाने का। आप बताइए कि ठीक है मेरी बात या नहीं?

धुंधलाती स्मृतियां

हा

ल ही में सामने आए आंकड़ों के अनुसार जापान में स्मृति भ्रंश यानी याददाश्त खो देने की समस्या एक बड़ा संकट बनती जा रही है। गौरतलब है कि जापान में वर्ष 2024 में स्मृति भ्रंश से पीड़ित लगभग अठारह हजार उम्रदराज लोग अपने घर का रास्ता भूल गए। याददाश्त खोने या कमजोर होने से बुजुर्गों का भटक जाना समग्र समाज के लिए एक चंतावनी बनकर सामने आया है। तकलीफदेह है कि अपने ही आंगन तक पहुंचने का मार्ग भूलें बुजुर्गों में से पांच सौ लोगों के शव लावारिस हालत में मिले। ऐसे में वहां स्मृति भ्रंश के शिकार लोगों के बढ़ते आंकड़े गहन चिंता का विषय बन गए हैं।

स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति के रूप में देखा जाए या जीवन से जुड़ी आवश्यक बातों और हालात को भूल जाने के तौर पर, स्मृति भ्रंश दुनियाभर में हर आयुवर्ग के बीच एक गंभीर समस्या बन रही है। चिंतनीय यह भी है कि स्मृति भ्रंश की समस्या बहुत से लोगों में आगे चलकर मनोभ्रंश की व्याधि बन जाती है। मनोभ्रंश स्मृति भ्रंश की ही एक व्यापक स्थिति है, जिसमें याददाश्त कमजोर होने के साथ ही भाषायी, तार्किक और निर्णय लेने की क्षमता में भी गिरावट आ जाती है। वहीं स्मृति भ्रंश मुख्यतः याददाश्त कमजोर होने से जुड़ी परेशानी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर में साढ़े तीन करोड़ से भी ज्यादा लोग मनोभ्रंश से पीड़ित हैं। सन 2050 तक यह संख्या तिगुनी से भी अधिक बढ़कर साढ़े ग्यारह करोड़ तक पहुंच जाएगी।

विचारणीय है कि डिजिटल दुनिया में बीत रहे लंबे समय ने इंसान के मन-मस्तिष्क की कार्यशैली बदल दी है, जिसके चलते गुस्सा, चिड़चिड़ापन नौद की कमी और याददाश्त कम होने जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। एक ओर सोशल मीडिया मंचों की संख्या बढ़ी है, तो दूसरी ओर हर आयुवर्ग के लोग इन आभासी मंचों पर लंबा समय भी बिता रहे हैं। जरूरत से ज्यादा स्क्रीन पर रमने के चलते मन ही नहीं, मस्तिष्क पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। अधिकतर लोग एक तरह के भावनात्मक संक्रमण, सूचनाओं की अति और जरूरी या गैरजरूरी जानकारी के अंबार तले दबे हैं। यह स्थिति भी स्मरण शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। स्पष्ट दिखता है कि तकनीकी सुविधाओं के घेरे में इंसान शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी निष्क्रिय हो रहा है। सोचने-समझने की घट रही शक्ति से दिमाग की कार्यप्रणाली शिथिल हो रही है। यही नहीं, आभासी संसार में हर पल विचित्र सामग्री देखते रहने से भी अकेलापन, अवसाद, चिंता और दिमागी सुस्ती बढ़ रही है। इन हालात में तार्किक और भावनात्मक मोर्चे पर हिस्से आ रही उलझन दिमागी विघटन का सबसे बड़ा कारण साबित हो रही है, जो सीधे-सीधे मस्तिष्क की कार्यक्षमता पर दुष्प्रभाव डालने, मन को मायूसी में घेरने और व्यवहार में असंयम तथा अस्थिरता लाने वाली है।

दरअसल, तकनीकी तरक्की ने दृश्य माध्यमों की भूमिका बढ़ा दी है। हर मुट्ठी में मौजूद जानकारी की स्क्रीन ने दिमाग पर जोर डालकर सोचने और याद रखने की जरूरत ही कम कर दी। क्लिक भर में स्क्रीन के माध्यम से मिलती या टूटती जाती हर सूचना-विवरण या तस्वीर दिमाग को सुस्त बनाने वाली गतिविधि साबित हो रही है। सामाजिकता का दायरा घटा है। शारीरिक-मानसिक और सामाजिक गतिविधियों में कमी स्मृति कम होने के जोखिम को और बढ़ा रही है। कुछ समय पहले एप से टैक्सी उपलब्ध करवाने वाली एक कंपनी द्वारा देश के पांच शहरों में किए गए सर्वे में लोगों की याददाश्त कमजोर होने की बात सामने आई थी, जिसमें मुंबई पहले नंबर पर रहा।

असल में इंसानों के लिए याद रखने के नाम पर स्मृतियां भर नहीं होतीं। रोजमर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ याद रखना जरूरी होता है। मन-मस्तिष्क की सजगता के बिना संवाद-प्रतिवाद से लेकर दैनिक कामकाज को पूरा करने

तक अनगिनत मुश्किलें सामने आती हैं। ऐसे में आम जीवन से जुड़ी सहज-सी गतिविधियों, सामान और कामों की सूची को भी भूल जाना एक बड़ा खतरा बन गया है। कमजोर होती स्मरण शक्ति दुर्घटनाओं तक को न्योता देने वाली साबित हो रही है। बच्चे हों या बड़े, पल भर में यह भूल जा रहे हैं कि उन्होंने क्या काम करने के बारे में सोचा था! अपना फोन नंबर या पता याद रखना मुश्किल हो गया है। अब न रास्ते याद रहते हैं और न ही किसी तरह के सीमा चिह्न। घर-परिवार में भी चीजों को रखकर या बातों को बोलकर भूल जाने की समस्या ज़िंदगी को हर मोर्चे पर मुश्किल बनाने लगी है। चिंता का विषय है कि अब यह जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे बुजुर्गों की परेशानी भर नहीं रही। हमारे देश में भी कम उम्र के लोग कमजोर होती याददाश्त के मरीज बन रहे हैं। एकल परिवारों के इस दौर में भूल जाने की स्थितियां बहुत से



समाज

मोनिका शर्मा

इं सानों के लिए याद रखने के नाम पर स्मृतियां भर नहीं होतीं। रोजमर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ याद रखना जरूरी होता है। मन-मस्तिष्क की सजगता के बिना संवाद-प्रतिवाद से लेकर दैनिक काम को पूरा करने तक अनगिनत मुश्किलें सामने आती हैं। ऐसे में आम जीवन से जुड़ी सहज-सी गतिविधियों, सामान और कामों की सूची को भी भूल जाना एक बड़ा खतरा बन गया है।

जोखिम पैदा करने वाली हैं। तकनीक से घिरती जीवनशैली में कुछ सकारात्मक बदलाव ही इस समस्या से बचाने में मददगार बन सकते हैं।

धुंधलाती स्मृतियों की व्याधि से जूझने के लिए मन-मस्तिष्क को सजग-सक्रिय रखना आवश्यक है। तकनीकी सुविधाओं की सहायता लेने के बजाय इरादतन कुछ सूचनाएं याद रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही 'डिमेंशिया' को लेकर सरकार को भी देखभाल से जुड़ी उचित नीतियां बनानी होंगी। गौरतलब है कि जापान में सरकार ने स्मृति भ्रंश की व्याधि से जुड़ी संभाल-देखभाल को सबसे जरूरी नीतियों में से एक माना है। वहां भूलने की समस्या से निपटने के लिए तकनीक का सहारा लेने का भी निर्णय लिया गया है। कमजोर याददाश्त से पीड़ित लोगों को जीपीएस ट्रेकिंग सुविधा, रोबोटिक सहायक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एआई जैसी तकनीकों के माध्यम से नजर रखने, पहचानने और भावनात्मक सहारा देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि तकनीकी सुविधाएं मानवीय देखभाल का विकल्प नहीं बन सकतीं। भारत में तो सामाजिक-पारिवारिक ताने-बाने को सहेजना क्षीण होती स्मरण शक्ति वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी है। साथ ही कुछ नया सीखना, प्राकृतिक परिवेश से जुड़ना और शारीरिक गतिविधियां इस व्याधि से दूर रखने में मददगार बन सकती हैं। तकनीकी विस्तार के दौर में जीवनशैली में प्रभावी बदलाव के बिना स्मरण शक्ति कम होने की समस्या से नहीं जूझा जा सकता।

भारत के पराक्रम की गाथा

मुकेश चौरसिया

आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति में एक निर्णायक पड़ाव बनकर उभरे 'आपरेशन सिंदूर' की चर्चा रह-रहकर होती रहती है। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिजित तबों को लेकर देश में विपक्षी दलों के नेता आपरेशन सिंदूर पर अनर्गल प्रलाप में लगे रहते हैं। ऐसे में इस महत्वपूर्ण सैन्य अभियान की सच्चाई को दुनिया के सामने रखना बेहद आवश्यक है। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवा.) केजेएस 'टाइनी' हिल्लों ने अपनी कलम से यह ब्रीड़ा उठाया है। सैन्य प्रतिष्ठान के साथ गहन जुड़ाव रखने और कई सफल अभियानों का हिस्सा बने हिल्लों का अपना अनुभव इस महत्वपूर्ण अभियान की दस्तान में बखूबी झलकता भी है। यह पुस्तक परमाणु शक्ति संपन्न दो देशों के बीच करीब चार दिन तक चले संघर्ष की बारीक जानकारी, घटनाक्रम और विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है।

22 अप्रैल, 2025 का दिन भुलाया नहीं जा सकता, जब जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में नृशंस आतंकी हमला हुआ था। टैपहर करीब ढाई बजे भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने पर्यटकों पर सुनिश्चित हमला किया था। इसमें 26 निर्रक्ष लोग की जान गई थी। टैरेंजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने हमले की जिम्मेदारी

ली थी, जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है।

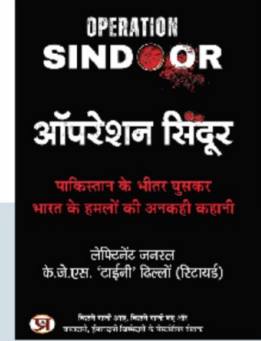
पुस्तक में बताया गया है कि किस तरह इसका बदला लेने के लिए बहुत खामोशी के साथ तैयारी की गई। इस दौरान सरकार ने आवेगपूर्ण या राजनीतिक रूप से उत्तेजित बयान देने से परहेज किया। यह संयम नेतृत्व का सोचा-समझा फैसला था। जवाबी कार्रवाई के लिए खुफिया जानकारी को जांच-परखकर पुख्ता किया गया। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए चुना गया। इन लक्ष्यों को चुनने के पीछे तर्क यही था कि पहलगाम हमले और सीमा पार आतंकी गतिविधियों में शामिल आतंकी संगठनों के साथ इनकी पक्की मिलीभगत थी। आपरेशन की पूरी योजना को अंतिम रूप दिया गया और सर्वोच्च स्तर से राजनीतिक मंजूरी ली गई। इस अभियान के लिए 'आपरेशन सिंदूर' नाम चुना गया, जो उन महिलाओं को पहंची क्षति का बदला लेने का देश के प्रण का संकेत था, जिनकी मांग उजाड़ी गई थी।

'आपरेशन सिंदूर' के तहत सात मई को नौ आतंकी अड्डों को सटीकता और समन्वय के साथ निशाना बनाया गया। इन लक्ष्यों में से सात पर सेना और दो पर वायुसेना ने पूरे समन्वय के साथ हमला किया। सेना ने मध्यम दूरी के हथियार

यह पुस्तक भारत द्वारा पाकिस्तान पर आतंकवाद के विरुद्ध सफलतापूर्वक चलाए गए आपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम एवं उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है...

पुस्तक : आपरेशन सिंदूर
लेखक : लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस 'टाइनी' हिल्लों (रिटायर्ड)
प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन
मूल्य : 600 रुपये

प्रणालियों का प्रयोग किया तो वायुसेना ने राफेल, मिग-2000 एवं सुखोई 30 एमकेआइ लड़ाकू विमानों और उन्नत मिसाइलों का प्रयोग किया। पाकिस्तान के जवाबी हमलों का सामना करने के लिए भी पूरी तैयारी की गई थी। इसके लिए एकीकृत वायु रक्षा ग्रिड पूरी तरह तैयार था। इस व्यापक रक्षा नेटवर्क में उन्नत एस-400 मिसाइल सिस्टम के साथ कई स्तरों पर वायु रक्षा हथियार तैनात थे। इन्होंने पाकिस्तानी मिसाइल खतरों का प्रभावी ढंग से पता लगाया और रोक दिया। भारत ने 10 मई को पाकिस्तान में अंदर तक उसके एयरबेस को इस प्रकार निशाना बनाया कि वह सहम गया और



उसे संघर्ष विराम के लिए मांग करनी पड़ी।

'आपरेशन सिंदूर' ने भारत की रणनीति को आतंकवाद और पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण आक्रामकता के विरुद्ध पूरी तरह बदल दिया है। इस निर्णायक सैन्य अभियान ने न केवल भारत की सटीक और प्रभावी जवाबी कार्रवाई की क्षमता को प्रदर्शित किया, बल्कि इसने रक्षा सिद्धांत में भी महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया है। पुस्तक में छह अध्यायों के जरिये पाकिस्तान के छद्म युद्ध, आतंकवाद पर उसकी नीति और आपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी के अलावा भविष्य की राह पर प्रकाश डाला गया है।

Dainik Jagaran Page No-9

कोई भी देश चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अपनी इच्छा थोप नहीं सकता : जयशंकर

पुणे, ६ : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को कहा कि आज दुनिया भारत को ज्यादा सकारात्मक नजर से देखती है, और देश की छवि में यह बदलाव ऐसी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। दुनिया में सत्ता व प्रभाव के कई नए केंद्र उभरे हैं। कोई भी देश चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सभी मुद्दों पर मर्जी थोप नहीं सकता। भारत ने मानव संसाधन में सफलतापूर्वक तरक्की की है, जबकि कई विकसित देश ठहराव व जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहे हैं।

पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीमंड यूनिवर्सिटी) के 22वें दीक्षा समारोह में जयशंकर ने यह भी कहा कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आया है। "दुनिया अभी हमें कैसे देखती है? इसका सीधा जवाब है कि पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा सकारात्मक और ज्यादा गंभीरता से, और इसके कारण हैं हमारा नेशनल ब्रांड और हमारी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा -

विदेश मंत्री बोले - दुनिया की आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है

एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा - दुनिया में सत्ता एवं प्रभाव के कई नए केंद्र उभरे हैं



एस. जयशंकर।

फाइल

जिसमें सुधार हुआ है।" आज दुनिया भारतीयों को ऐसे लोगों के तौर पर देखती है, जिनकी कार्य नीति अच्छी है, जिनमें टेक्नोलॉजी की काबिलियत है और जो परिवार-केंद्रित संस्कृति को मानते हैं। जयशंकर ने कहा, "विदेश में बातचीत

'भगवान कृष्ण व हनुमान सबसे बड़े राजनयिक थे'

पुणे, एएनआई : भारत की अपनी परंपराओं पर जोर देते हुए और धर्मग्रंथों में रणनीति एवं राजकाज के उदाहरणों को उजागर करते हुए जयशंकर ने कहा कि भगवान कृष्ण और भगवान हनुमान भी "सबसे बड़े राजनयिक" थे। एक महाभारत की कहानी के महान राजनयिक हैं, जबकि दूसरे रामायण के महान राजनयिक हैं। पुणे बुक फेस्टिवल में उन्होंने यह भी कहा कि आज की दुनिया गठबंधन की राजनीति का दौर है। बहुध्रुवीय दुनिया कई पार्टियों की तरह है... कभी आप एक के साथ होते हैं, तो किसी दूसरे मुद्दे पर आप दूसरे के साथ होते हैं।

के दौरान मुझे ज्यादातर अपने डायस्पोरा के लिए तारोंफ के शब्द सुनने को मिलते हैं। जैसे-जैसे भारत में बिजनेस करने व रहने में आसानी बेहतर हो रही है, वैसे-वैसे एक देश, समाज और लोगों के तौर पर पुरानी रूढ़िवादिता पीछे छूट रही है।

मशहूर न होने के फायदे

हास्य-व्यंग्य



मशहूरी का अपना आकर्षण है। समय बदलने के साथ मशहूर होने के तरीकों में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। पहले लोग सहज और स्वाभाविक रूप से मशहूर होते थे। अब दिन-दहाड़े 'वायरल' होते हैं। तब आदमी प्रतिभा और कौशल दिखाकर प्रसिद्धि पाता था, पर अब 'वायरल' होने के लिए अधिक सनकपन और थोड़ी उछलकूद चाहिए। इसमें लंबे समय या कठिन श्रम की जरूरत नहीं पड़ती। अचानक कोई मूर्खता से भरा कृत्य करके इंटरनेट पर परोस दीजिए, फटाफट मशहूरी मिल जाएगी। हालांकि यह जितनी जल्दी मिलती है, उससे भी जल्दी गुम होती है।

अब सबका मिशन एक है, 'ट्रेंड' होना और यह सपना देखना कि एक बार हो गए, तो जिंदगी संवर जाएगी। मशहूर होने का फायदा एक है पर न होने के अनेक। प्रसिद्धि पाने पर वह आम आदमी नहीं रहता। इस एक वजह से उसे किसी लाइन में नहीं लगना पड़ता। उसके सारे काम पलक झपकते होते हैं। इसके उलट मशहूर होने के नुकसान बहुत हैं। वह ठेले पर गोलगप्पे नहीं खा सकता। गुमटी में बैठकर कॉफी चाय नहीं पी सकता और न ही सब्जी वाले से मोल-तोल कर सकता है। जो मशहूर नहीं है, वह बिंदीस घूमता है। खुलकर डकार ले सकता है और रिश्तेवाले से दो रुपये के लिए हील-हुज्जत भी कर सकता है। हाँ, मशहूर न होने का एक नुकसान भी है। कुछ



संतोष त्रिवेदी

किसी के मशहूर होने पर लोगों की निगाहें उसी पर लगी रहती हैं। मुद्दा होया आदमी, सामान्य होने में ही भलाई है

गलत होने पर सिपाही कभी भी उसे पीट सकता है। सरकारी कार्यालय में जरूरी काम के लिए वह गैर-जरूरी धक्के खा सकता है। उसकी कही बात का कोई वजन नहीं होता। कुल मिलाकर मशहूर न होना आम आदमी के लिए कहीं बेहतर है। उसे नौद भी अच्छी आती है। मशहूर न होने के इतने फायदे हैं, फिर भी साहित्य और सियासत में आए दिन लोग मशहूर होना चाहते हैं। सियासत में मशहूर होना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए बस इतना जरूरी है कि काम न करके केवल उसका शोर मचाया जाए। एक-दो उल्टे-सोढ़े बयान देकर तुरंत मशहूर हुआ जा सकता है। हजार-पांच सौ साल से गड़ा मुद्दा उखाड़कर उसे जिंदा किया जा सकता है। साहित्य में इतनी अधिक सुविधा नहीं है। वहाँ लिख-लिखकर मशहूर होना बहुत दूर की कौड़ी है। इसके लिए एक नया उपाय किया जा सकता है। अपनी दो कौड़ी की किताब को कीमत

तीन करोड़ रख दीजिए। हर तरफ इसके चर्चे होंगे। किताब तो कोई नहीं लेगा। हाँ, आप 'मशहूर' जरूर हो जाएंगे।

तुरंत प्रसिद्धि पाना उनके लिए सरल है जो अधिक चतुर हैं। एक सामान्य बुद्धि वाला ऐसे में क्या करे? इसके लिए 'रील' है ना। जितनी ऊटपटांग हरकत होगी, उतनी ही रील वायरल होगी। अब तो मनींतियाँ तक हो रही हैं कि काश, एक रील ऐसी निकल आए। मशहूरी पा जाने पर फिर वह और भी मूर्खतापूर्ण रील बनाने लगता है। इससे निष्ठलले लोगों का मनोरंजन होता है और 'रीलर' रोज डालर गिनता है। जबसे रुपये को मशहूरी मिली है, वह कहीं का नहीं रहा। जल्द ही वह बेरोजगारी और महंगाई की तरह नगण्य हो जाएगा। विशेषज्ञ उसकी कमजोरी के भी फायदे बताने लगेंगे। इसलिए ज्यादा मशहूर होना खतरों से खाली नहीं है। लोगों की निगाहें उसी पर लगी रहती हैं। मुद्दा हो या आदमी, सामान्य होने में ही भलाई है। ऐसे में सरकार अपना काम करती रहती है। देखिए न, धुंध और प्रदूषण मशहूर होने की सजा भुगत रहे हैं। ऐसे मौसम में नेताओं को 'आइव्यू' और 'एआइव्यू' में कन्स्यूजन पैदा हो जाता है। अच्छी बात यह है कि जब नेता विपक्ष में होते हैं तो उन्हें गहरी धुंध भी साफ नजर आती है। सता में आते ही यही धुंध उनकी आँखों में चढ़ जाती है। सियासत की यह सबसे बड़ी मशहूरी है।

response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

8 of 15

बांग्लादेश में भारत के लिए खतरा बढ़ा



दिव्य कुमार सोती

बांग्लादेश में जमाती और युनुस सरकार के घटक ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहे हैं, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा बंगाल, ओडिशा और बिहार तक शामिल हैं

बांग्लादेश में स्थिति सुधरने के स्थान पर बिगड़ने की ओर है। पहले समझा गया था कि चुनावों की घोषणा के साथ यह देश स्थिरता की ओर बढ़ेगा, पर चुनावों की घोषणा के कुछ घंटों के भीतर ही कट्टर इस्लामिक विचारधारा से जुड़े छात्र नेता शरीफ उदमान हादी पर दका में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा हमला कर दिया गया। हादी ने सिंगपुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। उस पर हमले के बाद से ही बांग्लादेश में भारत और अबामा लोग के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू हो गए।

हादी की शिक्षा एक मद्रसे में हुई थी। वह एक कट्टरपंथी मौलाना का बेटा था। अतिवादी जिहादी विचारधारा के चलते ही उसने कुछ दिन पहले भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने वाले बयान दिए थे। उस पर गैली चलाने वाले जानते थे कि हमले का आरोप भारत पर लगेगा और यही हुआ भी। हादी पर हमले का उद्देश्य फरवरी में चुनाव न होने देने का संकेत है, क्योंकि चुनाव होने पर अमेरिकी पिट्ट माने जाने वाले मोहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को जाना होता। हालांकि खालिद जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी चुनाव जीतने की स्थिति में है, परंतु अमेरिकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों द्वारा पुनर्जीवित इस्लामिक

कट्टरपंथी शक्तियों को अब खालिद बूदी और कमजोर लगती हैं। उन्हें लगता है कि वे भारत के विरुद्ध एक संरमा से आगे नहीं जा सकती। वे बहुत अस्वस्थ हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। लंदन में रह रहे उनके बेटे तारिक अनवर बांग्लादेश का नेतृत्व करने के लिए बांग्लादेश लौट सकते हैं, पर वे समाजिक विकास की योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, न कि भारत विरोध और कट्टरपंथ के नाम पर। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी और खालिद जिया की बांग्लादेशी दशकों से गठबंधन में रहे हैं, पर अब वह टूट चुका है। जमात के पाकिस्तानपरस्त कट्टरपंथियों को लगता है कि उनके पास सत्ता पाने का मौका है। बांग्लादेशी इस्लामिक कट्टरपंथियों के प्रति नरम रवैया रखने के बावजूद 1971 के मुक्ति संग्राम को पवित्र मानती हैं। वहीं जमात बांग्लादेश बनने की इस्लामिक एजेंडे के साथ धोखा मानती है। उसके नेता पाकिस्तान के साथ एकीकरण चाहते हैं। 1971 में तो उसके नेता पाकिस्तान को फौज के साथ मिलकर मुक्ति बाहिनी और भारतीय सेना से लड़े भी थे। अब वे बांग्लादेश की जगह शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह से उपजी नई पार्टियों जैसे हादी के इंकिलाब मंच के साथ बांग्लादेश पर राज करने का सपना देख रहे हैं।



हादी ने पिछले दिनों बांग्लादेश की भी धमकी दी थी कि अगर भारत के प्रति जरा भी नरम रवैया दिखाया तो उसकी सरकार वैसे ही पलट दी जाएगी, जैसे अबामा लोग की पलट गई थी। हादी और जमाती अमेरिकीपरस्त नई राजनैतिक शक्ति नेशनल सिटीजन पार्टी पुनर्सीपी की भी आँखें देख रहे थे। पुनर्सीपी में बही छात्र नेता हैं, जिन्होंने शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। साफ है कि बांग्लादेश के अंदर ही बहुत सी शक्तियों के पास हादी की हत्या करने के कारण थे, पर मोहम्मद युनुस सरकार ने यह प्रोपेगंडा चलने दिया कि हादी की हत्या भारत ने करवाई है और उसके हत्यारे भारत भाग गए हैं। इसके बाद से भारतीय उच्चायोग के दिकानों पर हमले शुरू हो गए। कट्टरपंथियों की भीड़ ने बांग्लादेश के दो सबसे बड़े अखबारों 'द डेली स्टार' और 'प्रोथेम आला' को भारत का एजेंट बताते हुए उनके दफ्तरों को जला दिया। बांग्लादेश की फौज यह सब देखती रही। उसने कट्टरपंथियों की भीड़ पर बरंबाई नहीं की। भीड़ ने एक हिंदू युवक को

पीट-पीटकर मार डाला और उसकी लाश को चौराहे पर लटकाकर जला डाला। अब अगर यह अस्थिरता आगे बढ़ती है तो युनुस के पास फरवरी के चुनाव टालने का एक बहाना होगा। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टियों को सहानुभूति मिलेगी और उनकी सौटें बढ़ जाएंगी, जिसके चलते चुनाव बाद बांग्लादेश के किसी भी गठबंधन में दोषम दर्जे की साझेदार रह जाने की संभावना बढ़ती है। भारत की समस्या बस इतनी ही नहीं है कि बांग्लादेश में अमेरिकीपरस्त पुनर्सीपी और पाकिस्तानपरस्त जमाती भावी सरकार को नेतृत्व करते दिख सकते हैं। जब शेख हसीना का तख्तापलट हुआ था तो उनके खिस्तेदार और बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जामा ने उन्हें सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया था। इससे भारत ने यह सोचकर रहत की सांस ली थी कि कम से कम सेना तो सही हाथों में है, परंतु उसके बाद से बांग्लादेश के सैन्य नेतृत्व ने निराश ही किया है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी सेना ने कट्टरपंथी भीड़ को प्रधानमंत्रि आवास में

घुसने दिया, जिसने वहां उनके अंत:करण तक केमरों के सामने लहराया। इसके बाद जब युनुस ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान को जन्मतिथि मनाने पर प्रतिबंध लगाया और जमातियों ने उनकी मजार पर जाने वालों को पीटा तो भी वकारुज्जामा ने कुछ नहीं किया। क्या बांग्लादेशी सैनिकों का एक बड़ा धड़ा जमात के प्रभाव में है और वकारुज्जामा इस कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थन में मजबूर हैं? प्रश्न यह भी है कि क्या बांग्लादेश की भारत की संरमा पर खरिया जैसे इस्लामिक गुहयुद्ध से ग्रस्त क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ भाँति-भाँति के इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पनप सकें?

बांग्लादेश में इस समय जमाती और युनुस सरकार के घटक ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहे हैं, जिसमें म्यांमार का रखडन प्रांत, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं बिहार तक के हिस्सों पर कब्जा करके सिराजुद्दीन की बंगाल सल्तनत की स्थापना होगी। हादी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर स्वयं इस आशय के पोस्ट किए थे। यह सब हास्यास्पद लग सकता है, पर इस पागलपन में करोड़ों बांग्लादेशी विश्वास करते हैं और यह स्थिति बांग्लादेश की जिहाद का नया मंच बन देने के लिए कामी है। इसका अर्थ होगा भारत की पूर्वी सीमा पर भी पाकिस्तान की ही तरह एक आतंकी देश का उभरना और वहाँ रह रहे 1.30 करोड़ हिंदुओं के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल होगा।

(लेखक कार्टिस्त आर स्टूडेंटिक अपेयस से संबंध सामरिक विश्लेषक हैं) response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8



यह ठीक है कि भारत और चीन की सत्ता प्रणालियों में खासा फर्क है, लेकिन इसे कुछ न करने की वजह के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर हमने प्रदूषण की रोकथाम के लिए तत्काल कुछ बड़े कदम न उठाए, तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ गंवाने पर विवश होना पड़ेगा।



अजय शर्मा के लिए
प्रकाशित आलेखों के लिए

हवा में पसरे जहर से जूझना होगा

शशि शेखर

बारों पहले दक्षिण अफ्रीका के 'काला पानी' रॉबिन आइलैंड में नैल्सन मंडेला को कोठरी देखा था। 17x9 के उस पिंजरेनुमा कमरे में छह फुट मंडेला ने अपनी जखनी के 18 साल काटे थे। मंडेला के अंतिमारे को मारी इस निस्तेज कोठरी में वह प्रतिदिन कसलत के जरिये तन-मन को टुटल रखने का प्रयास करते।

अलग-अलग कारागारों में मंडेला कुल जमा 27 साल कैद रहे। इस बड़े अंतराल में दुनिया ने न जाने कितनी करवटें लीं, पर मंडेला इस अंतर्गत अकेलेपन में भी अपनी अखंड को जमा को तस-मिलाने रखने में कामयाब रहे। आजकल वह बहुत बाद आने लगे हैं। इसकी वजह उनका त्याग, योग्य और सिद्धांतों के प्रति समर्पण नहीं, बल्कि वाकफोरी है, जहां मंडेला सज्जन कटने के साथ खुद को चुल-दुल रखने की लयवा कर रहे थे। दिल्ली और राठौर राजधानी क्षेत्र में जहरीली हवा ने आजकल मुझ जैसे क्षेत्री लोगों को घर में ही टहलने या कसरत करने के लिए मजबूर कर दिया है।

मिछले रविवार को तो गजब ही हो गया। सुबह कुछ देर से उठा और बालकनी से बाहर झांका, तो सन रह गया। नोएडा के मेरे 17वीं मंजिल पर स्थित अपार्टमेंट से नीचे धरती नहीं दिख रही थी। हमारी सरजमीं और हमारे बीच महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आसमान से बादल नीचे उतरते हैं, परंतु वह धुंधलका तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। अनीब-सी दहशत ने मुझे घेर लिया था, पर मैं अकेला नहीं था। मुझ जैसे लाखों लोग जानते थे कि यह एक झूठे सपने का बहुत दुर्ग अवसान मात्र है। आगे भी हाल बेहाल रहने वाला है।

बड़े अन्वयर्ष नहीं कि दिल्ली और पुरानी आर में इन दिनों मिर्ग बिथली वायु के चर्चे हैं। बड़े सांस नहीं ले पा रहे, नौजवानों का दम घुट रहा है, गर्भवती युवावस्था बाहर निकलने से कतरा रही है और नवजात शिशु वृषेन हैं। हर नागरिक

आने पर में 'एयर प्युरीफायर' तो लगवा नहीं सकल और जो लगवा चुके हैं, वे भी खूब को कितनी देर बंद बिडुकिनी और दरवाजों के पीछे रख लेते? मंडेला को रंगभेदी उपनिवेशवादी सरकार ने जेल में डाला था, पर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में वह दंडा भोगने को अभिमत हैं।

मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?

अब तक हमारे देश में पर्यावरण को लेकर चिंता तो जाहिर की जाती रही, लेकिन उपाय 'ऊंट के मुंह में जिर' के बाबर ही किए गए। मसलन, 1999 में दिल्ली में सीएनजी बसें चलनी शुरू हुईं, कुछ प्रदूषण घटा और तालियां बगने लगीं। हालांकि, हमारे नीति-निर्णयता जानती थे कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला। पर-नकीकत आज भी लाखों लोग खाना बनाने और अपनी ठेक को यात्रा रखने के लिए एकटो या दोपहले का उपेय करते हैं। छोटे उद्योगों में भी टक्का उपेय होत

आजकल

है। विदेशी वाहन निर्माता पश्चिमी देशों और भारत जैसे मुलकों के बीच कानून उल्लंघन संबंधी रिसर्च का द्वैत बनाए हुए हैं। जो किसान कल पराली जलते थे, उन्हें आज तक पराली प्रवेदन के लिए संपूर्ण विकल्प मूहया नहीं कराए गए। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संख्या में पैड कर रहे हैं, उनको जगह कई गुना पैसे लगाए जाने का प्राधान्य है। वे समूचा आकार ले सके, इसको जिम्मेदारी कोई नहीं लेता।

क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर हमारी संस्कृति और विधानमंडल जरूरत के मुताबिक संवेदनशील हैं? व्यर्थ के मुद्दे पर शब्दबाण दानते रियासती विरादरी को अपने पर्यावरण के मुद्दे पर कभी ध्यानित करने देखा है? अकल्य नहीं है कि हमारे गवर्नरों अब सुट्टी के दिवार भरे लगे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री से हर परिचर्चा में यही सवाल पूछा जात है। अरविंद केजरीवाल से भी लगताच यह प्रश्न किया जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली पर लगतार 10 साल गान किया, रेखा गुवा तो अभी आई हैं।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि 'जलन्तवा बचा-



पानी के लिए सभी जल बाबर के निमेषदा है।

मैं यहां चीन का उदाहरण देना चाहूंगा। उसने वायु प्रदूषण पर कैसे काबू पाया, इस बारे में जान-बुझकर कम चर्चा की जाती है। यहां मैं अपनी आंखों देखा बताना चाहूंगा। सन 2008 में मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ बीजिंग गया था। एक साल पहले ही विश्व बैंक ने इसे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में एक घोषित करते हुए अनुमान लगाया था कि इस महानगर में हर साल चार लाख लोग प्रदूषण की वजह से मारे जाते हैं। हम जब वहां पहुंचे, तब हर ओर ओलीफिक की ठेकारों जैरी पर थीं। स्टैंडम बन रहे थे, रहने के ठिकाने संवारे जा रहे थे और इन्फ्रास्ट्रक्चर टूटने लगा था। नतीजतन, हर तरफ धूल हो धूल थी।

पश्चिमी मीडिया अक्षरों का जता रहा था कि ओलीफिक प्रतिभाषिणी और दर्शकों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। वे सतत न थे। ओलीफिक के दौड़न 10 अक्षरों को बीजिंग का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एय्क्यूआई) 604 दर्ज किया गया, जबकि उसी दिन लंदन में 38 और न्यूयॉर्क में 24 एय्क्यूआई आंका गया था।

आने वाले पांच साल में हालत और खराब हो गए। 'अमेरिकन एंजोसिलेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस' पेश किए गए अध्ययन के आंकड़ों के मुताबिक, 2013 में लाखों लोग चीन में पर्यावरण प्रदूषण के शिकार बने थे। 1: दौड़न बीजिंग का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एय्क्यूआई) 72 पर कर गया था। यही वह कुसंख्या था, जब खरों के सप्तमस्त न कर सकी। उन्होंने प्रदूषण से जमा के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई और भारी-भरकम बाजट निर्धारित किया। पेट्रोल, डीजल से चलने वाली कारों को सीधी खरीद पर रोक लगा दी गई। 3 ऐसी कारें खरीदने के लिए, सीमित लॉटरी का विकल्प उपलब्ध था। कार खरीदने के इच्छुक लोगों को इलेक्ट्रिक वा आसानी से उपलब्ध कराए गए और पानी आबादी वाले श में ट्रकों का प्रवेश बर्जित कर दिया गया। कोयले से चलने वा मशीनों का इस्तेमाल कम किया गया। साथ ही मेट्रो, रैपिड और नगर यातायात के अन्य संसाधनों को भारमा कर दी ग साइकिल संस्कृति को फिर से बढ़ावा दिया गया और काजग मिले, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरीयें बड़े शहरों से हटा दी ग शासन तंत्र को कसने के लिए राण्यवाली और महापौरों भी प्रदूषण नियंत्रण लक्ष्य से जोड़ा गया।

आज का चीन बाबर की तरह निरंकुश है। को सौर सज्जिया गया तक सीमित नहीं है, यहां नग्न पर प्रदूषण नियंत्र और प्रवेदन होता है। इसके लिए सज्जिया नगरपालिका तंत्रित न काम करता है। नतीजा समुद्र का एय्क्यूआई 460 बता रहा था, जब बीजिंग में उस वक्त 73 एय्क्यूआई दर्ज था। टीक उसी समय दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की प्रवक्ता वू यिंग ने 'एक्स' लिखा, 'भारत और चीन, दोनों ही तेजी से बढ़ते शहरीकरण बीच वायु प्रदूषण से जुड़े हैं। हालांकि, चुनौती अभी जटिल है, मगर पिछले एक दशक में चीन ने अपने लगातार प्रयासों से काफी सुधार दर्ज किया है।'

वह ठीक है कि भारत और चीन की सत्ता प्रणालियों में खा फर्क है, लेकिन इसे कुछ न करने की वजह के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर हमने प्रदूषण की रोकथाम के लिए तत्काल कुछ बड़े कदम न उठाए, तो आने वाले दिनों बहुत कुछ गंवाने पर विवश होना पड़ेगा।

@shekharkahn
@shashishekarjournalist

Hindustan Page No-16

प्रस्ताव

ग्रामीण कार्य विभाग तैयार कर रहा इंटीग्रेटेड रूरल रोड मटेनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, इससे सड़कों की निगरानी आसानी से होगी

तैयारी: जीआईएस तकनीक से ग्रामीण सड़कों पर नजर

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य की एक लाख से अधिक ग्रामीण सड़कों की देखरेख को ग्रामीण कार्य विभाग अब जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) तकनीक का सहारा लेगा। इसके लिए एक नई तकनीक इंटीग्रेटेड रूरल रोड मटेनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (आईआरएमएस-एकीकृत ग्रामीण सड़क रखरखाव निगरानी प्रणाली) लाई जा रही है। योजना को मूर्त रूप देने का प्रस्ताव जल्द ही राज्य कैबिनेट के समक्ष ले जाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही बिहार में इस प्रणाली पर

अमल होना शुरू हो जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आईआरएमएस प्रणाली के तहत ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। खासकर कौन सी सड़क किस स्थिति में है, किसकी मरम्मत की आवश्यकता है आदि की निगरानी सहज तरीके से हो सकेगी। इसी के आधार पर विभाग आवश्यक निधि का इंतजाम कर सकेगा। इस प्रणाली का एक लाभ यह भी होगा कि आमतौर पर सड़कों की स्थिति का आकलन करने, कार्यबल या प्राति को ट्रैक करने में परेशानी होती है।

178

करोड़ की परियोजना को मूर्त रूप देने का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा



ग्रामीण इलाकों में सड़क की सम्पर्कता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी

जीआईएस और मोबाइल एप्लिकेशन जैसी तकनीक से सड़कों की निगरानी आसानी से होगी। इस प्रणाली में

पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। रखरखाव कार्यों की दक्षता में सुधार होगा, जिससे ग्रामीण इलाकों में

1.20 लाख किमी है ग्रामीण सड़कें

बिहार में पिछले 20 वर्षों में राज्य की एक लाख 20 हजार 685 ग्रामीण बसावटों को पक्की बारहमासी सड़कों के नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। इसके लिए एक लाख 19 हजार 681 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। दो शक में 2683 पुल भी बने हैं। ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत राज्यभर में 37345 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का अनुरक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। लगभग 1500 किलोमीटर पथों में अनुरक्षण कार्य प्राति पर है।

सड़क की सम्पर्कता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। इस प्रणाली पर 178 करोड़ खर्च होने की उम्मीद है।

Hindustan Page No-12

आईसीडीएस की रिपोर्ट से सामने आई चिंताजनक स्थिति बक्सर और मधुबनी में बच्चे अतिकुपोषित



विशेष

सोमनाथ सत्योम

मुजफ्फरपुर। सूबे में बक्सर जिले के बच्चे सबसे अधिक अतिकुपोषित हैं। वहीं, उत्तर बिहार में मधुबनी के बच्चे सबसे अधिक अतिकुपोषित पाए गए हैं। इसका खुलासा बिहार सरकार की आईसीडीएस (इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज) के नवंबर माह के आंकड़ों से हुआ है। राज्य के विभिन्न जिलों में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण यानी अतिकुपोषित होने की दर 0.71 प्रतिशत से लेकर 5.54 प्रतिशत तक दर्ज की गई है।

आईसीडीएस के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर बिहार के नौ जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम व पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में अतिकुपोषित बच्चों की संख्या काफी है। इन जिलों में 2.05 से लेकर 4.98 प्रतिशत तक बच्चे अतिकुपोषित हैं। मधुबनी में पांच साल तक के बच्चों की संख्या 3,22,539 है, जिसमें 16,055 अतिकुपोषित मिले हैं। यह अनुपात 4.98 प्रतिशत है जो उत्तर बिहार के जिलों में सबसे अधिक है।

वहीं, सीतामढ़ी में सबसे बेहतर स्थिति है। यहां कुल बच्चों में से 4,802



- रिपोर्ट के मुताबिक, बक्सर जिले में 1.12 लाख में से 6222 बच्चे कुपोषित मिले
- मधुबनी में 3,22,539 बच्चों में से 4.98 फीसदी अतिकुपोषित
- उत्तर बिहार के नौ जिलों में सबसे कम अतिकुपोषित बच्चे सीतामढ़ी में मिले

उत्तर बिहार के जिलों में अतिकुपोषित बच्चों की संख्या

जिला	संख्या	अतिकुपोषित	प्रतिशत
बक्सर	1,12,347	6,222	5.54%
शिवहर	53225	1676	3.15%
मुजफ्फरपुर	347001	11492	3.31%
वैशाली	263190	8847	3.36%
प. चंपारण	253162	8880	3.51%
समस्तीपुर	339621	13674	4.03%
दरभंगा	238972	9762	4.08%
पूर्वी चंपारण	317812	15400	4.85%
मधुबनी	322539	16055	4.98%

ही अतिकुपोषित पाए गए हैं। उत्तर बिहार के नौ जिलों में मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पर है। यहां कुल 3,47,001 बच्चों में 11,492 यानी 3.31% बच्चे अतिकुपोषण के शिकार मिले हैं। आईसीडीएस की रिपोर्ट बाल विकास मिशन के कार्यों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

पटना, बेगूसराय में भी अतिकुपोषितों की संख्या अधिक: अतिकुपोषित बच्चों के मामले में बक्सर, गोपालगंज, बेगूसराय, मधेपुरा और पटना टॉप फाइव में शामिल हैं। बक्सर में 1,12,347 बच्चों में से 6,222 बच्चे अतिकुपोषित की श्रेणी में हैं, जो सबसे अधिक 5.54 प्रतिशत हैं।

प्रश्न (BPSC Mains Style)

आईसीडीएस (Integrated Child Development Services) की हालिया रिपोर्ट में बिहार के बक्सर एवं मधुबनी जिलों में बच्चों में गंभीर एवं मध्यम कुपोषण की चिंताजनक स्थिति सामने आई है।

इस संदर्भ में—

1. बच्चों में कुपोषण के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए।
2. बक्सर और मधुबनी जैसे जिलों में कुपोषण की अधिकता के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।
3. कुपोषण से निपटने हेतु केंद्र एवं राज्य स्तर पर आवश्यक नीतिगत और संस्थागत सुधार सुझाइए।

(शब्द सीमा: 400)

उत्तर लिखने का प्रारूप

भूमिका (Introduction)

- रिपोर्ट / डेटा / सर्वे का संक्षिप्त संदर्भ
- समस्या की गंभीरता और प्रासंगिकता
- विषय को मानव विकास / SDGs / संवैधानिक मूल्यों से जोड़ना

I. समस्या का स्वरूप / स्थिति का विश्लेषण

- प्रभावित क्षेत्र/जिले का संक्षिप्त उल्लेख
- समस्या की व्यापकता (सामान्य से गंभीर)
- क्षेत्रीय/सामाजिक विषमता का संकेत

II. बच्चों में कुपोषण के प्रमुख कारण

(बिंदुवार लिखें)

- आर्थिक कारण
- सामाजिक कारण
- स्वास्थ्य एवं मातृ कारण
- संस्थागत/प्रशासनिक कारण
- भौगोलिक एवं पर्यावरणीय कारण

III. कुपोषण के निहितार्थ (Implications)

- बच्चों के शारीरिक विकास पर प्रभाव
- मानसिक एवं शैक्षणिक प्रभाव
- दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव
- सामाजिक न्याय एवं समावेशिता पर प्रभाव
- SDGs एवं मानव पूंजी पर प्रभाव

IV. वर्तमान सरकारी प्रयासों का संक्षिप्त मूल्यांकन

- केंद्र सरकार की योजनाएँ
- राज्य सरकार / स्थानीय संस्थाओं की भूमिका
- क्रियान्वयन से जुड़ी कमियाँ

V. समाधान एवं सुधार (Way Forward)

(बहु-आयामी दृष्टिकोण)

- नीति स्तर पर सुधार
- संस्थागत सुधार
- सामुदायिक सहभागिता
- निगरानी एवं डेटा आधारित हस्तक्षेप
- दीर्घकालिक सतत रणनीति

निष्कर्ष (Conclusion)

- समस्या का समेकित पुनः उल्लेख
- सकारात्मक एवं भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण
- मानव विकास और राष्ट्र निर्माण से जोड़कर समापन